लीबिया पर कब्जे का साम्राज्यवादी मंसूबा

फिदेल कास्त्रो के सामयिक विमर्शों का संकलन

देश विदेश
पुस्तिका : पाँच

देश-विदेश पुस्तिका-5
जुलाई - 2011

लीबिया पर कब्जे का
साम्राज्यवादी मंसूबा

सम्पादक
उमा रमण

सहयोग राशि
10 रुपये

सम्पर्क सूत्र
देश विदेश
502/10, एस-1, साँई कॉम्पलेक्स
ब्लॉक-डी, गली नं. - 1
अशोक नगर, शाहदरा,
दिल्ली - 110093
फोन : 09818622601
E-mail: deshvidesh@rediffmail.com

मुद्रक
प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स
ए-21, झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया
जी.टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-95

उमा रमण द्वारा एस-1 साँई कॉम्पलेक्स, 502/10 अशोक नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110093 से प्रकाशित

विषय सूची

सम्पादकीय

लीबिया : मौत के सौदागरों का नंगा नाच 5

लीबिया पर कब्जा करने का मंसूबा 11

मानवद्रोही मौत का तांडव 14

नाटो का अपरिहार्य युद्ध (भाग-1) 17

नाटो का अपरिहार्य युद्ध (भाग-2) 23

नाटो युद्ध, झूठ और व्यापार 28

बराबरों की हिस्सेदारी 37

नाटो का फासीवादी युद्ध 40

बेहतर और ज्यादा समझदार 44

एक आग जो सबको जला सकती है 50

बर्बर और उपद्रवी उत्तरी अमरीका 53

संपादकीय

लीबिया : मौत के सौदागरों का नंगा नाच

मिस्र और ट्यूनीशिया में जन बगावतों के विषय में देश-विदेश पुस्तिका-3 के क्रम में इस बार हम लीबिया की ताजा घटनाओं पर फिदेल कास्त्रो की सामयिक टिप्पणियों की एक शृंखला का अनुवाद प्रकाशित कर रहे हैं। आधी सदी तक प्रबल साम्राज्यवाद-विरोधी भूमिका निभाने वाले, विश्वबंधुत्व और विश्व जनगण के हितों के पक्के समर्थक, फिदेल ने अपनी इन टिप्पणियों में अमरीकी साम्राज्यवाद और उसके नाटो सहयोगियों द्वारा लीबिया सहित पूरे अरब जगत के संसाधनों पर कब्जा जमाने के नापाक मंसूबों का बड़े ही बेबाक और धारदार लहजे में पर्दाफाश किया है। निश्चय ही, इससे पाठकों को अरब जगत के वर्तमान घटनाक्रम को सही परिप्रेक्ष्य में देखने-समझने में मदद मिलेगी।

ये टिप्पणियाँ एक टीकाकार के रूप में फिदेल द्वारा सहज विचार प्रवाह के रूप में क्रमशः लिखी गयी हैं, एक व्यवस्थित निबन्ध के रूप में नहीं। इसलिए लीबिया के मौजूदा हालात से जुड़े कुछ जरूरी तथ्यों की यहाँ चर्चा करना जरूरी है।

X X X

इस वर्ष की शुरूआत में अरब जगत को हिलाकर रख देनेवाली जनबगावतों की जो लहर ट्यूनीशिया और मिस्र से शुरू हुई थी, वह अमन, बहरीन, सीरिया, मस्कट, कुवैत और सऊदी अरब सहित कई देशों तक फैल गयी। लीबिया भी इससे अछूता नहीं रहा। फरवरी के मध्य में उसके पूर्वी प्रांत, बेंगाजी में विद्रोह फूट पड़ा। गद्दाफी ने इस विद्रोह का बर्बर दमन किया। पश्चिमी मीडिया ने कई अरब देशों में सुगबुगा रही बगावतों से ध्यान हटाते हुए, लीबिया में जनसंहार की खबरों और गद्दाफी के तानाशाह छवि को खूब बढ़चढ़ कर उछाला। झूठ की ऐसी आँधी बहायी गयी कि पूरी दुनिया का ध्यान लीबिया पर ही टिक गया। अरब देशों के अमरीकापरस्त शेखों के लिए यह सब काफी राहत देने वाला था। जिस सऊदी अरब

ने कुछ ही दिनों पहले बहरीन में बागियों का दमन करने के लिए अपनी सेना तैनात की थी, वही लीबिया की जनता के लिए घड़ियाली आँसू बहाते हुए अपने आकाओं से वहाँ ''मानवीय हस्तक्षेप'' की माँग करने लगा। अमरीका और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव बढ़ाया कि वह गद्दाफी के खिलाफ कठोर प्रस्ताव लाये।

26 फरवरी को सुरक्षा परिषद ने सर्व सहमति से प्रस्ताव 1970 पास करके लीबिया को हथियार और सैनिक उपकरण बेचने पर रोक लगा दी। तब ऐसा लगा कि देश में गृह युद्ध को दबाने के लिए गद्दाफी ने वायु सेना का प्रयोग किया उसे देखते हुए यह कदम उचित है। इसी बीच गद्दाफी के कई विश्वस्त सहयोगी विद्रोहियों से जा मिले। इनमें से कुछ लोगों ने लीबिया की अर्थव्यवस्था में अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कम्पनियों का प्रवेश दिलाने के लिए उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ लागू करवाने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। इनमें से एक प्रमुख नाम है महमूद जिब्रील, जो बेंगाजी के विद्रोहियों द्वारा गठित प्रान्तीय राष्ट्रीय परिषद के प्रमुख विचारक और दिशा-निर्देशक हैं। विकीलीक्स के खुलासों में अमरीका के साथ इनके साँठगाँठ के विस्तृत ब्यौरे मौजूद हैं।

जाहिर है कि कल तक गद्दाफी के विश्वास पात्र और सहयोगी रहे लोग हवा का रुख बदलते ही जन विद्रोह को साम्राज्यवादी मंसूबे पूरा करने की दिशा में मोड़ने लगे। इसी समय कई पश्चिम-परस्त और सीआईए से सम्बद्ध सैनिक अधिकारियों ने भी विद्रोहियों की अगुआई करने के लिए मोर्चा सम्भाल लिया। इसमें एक प्रमुख नाम था लीबियाई सेना के पूर्व कर्नल खलीफा हफ्तीर का जिसे 1990 से ही वर्जीनिया में सीआईए के दफ्तर से 10 किमी की दूरी पर शरण मिली हुई थी।

पश्चिम मीडिया ने लीबिया में गृह युद्ध और नागरिकों की मौत के बारे में भड़काऊ खबरें प्रसारित करना जारी रखा। पश्चिमपरस्त, सीआईए समर्थित बागियों के नये नेतृत्व ने विमान वर्जित क्षेत्र की माँग शुरू की। उन्होंने अरब लीग के नेताओं से सम्पर्क किया। अरब लीग के महासचिव अमर मूसा ने गद्दाफी के खिलाफ अरब लीग, अफ्रीकी यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलीजुली कार्रवाई की माँग की।

फ्रांस ने सभी स्थापित कूटनीतिक मानदण्डों को ताक पर रखते हुए फरवरी में ही बेंगाजी के विद्रोहियों को 'लीबिया की जनता का एकमात्र प्रतिनिधि' के रूप में मान्यता दे दी थी। जाहिर है कि यह किसी सम्प्रभु देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा के समान था। पहले से ही इराक और अफगानिस्तान में बुरी तरह फँसे होने के चलते अमरीका के लिए एक और युद्ध में उलझना भारी पड़ रहा था, लेकिन लीबिया की

अपार प्राकृतिक सम्पदा के लोभ में उसने अपनी सेना को कार्रवाई के लिए राजी कर लिया। इस तरह फ्रांस और अमरीका दोनों ही लीबिया पर अपना साम्राज्यवादी वर्चस्व स्थापित करने के लिए व्यग्र थे और लीबिया में 'विमान वर्जित क्षेत्र' का प्रस्ताव लाने के लिए सुरक्षा परिषद पर दबाव बना रहे थे।

17 मार्च को नाटो द्वारा प्रेषित 'उड़ान वर्जित क्षेत्र' का प्रस्ताव 1973 जर्मनी, चीन, रूस और भारत की चेतावनी को नजरअन्दाज करते हुए सुरक्षा परिषद ने पारित कर दिया। इस तरह फ्रांस और अमरीका ने 'उड़ान वर्जित क्षेत्र' लागू करने के लिए 'हर तरह के तौर-तरीके अपनाने' तथा नागरिकों की रक्षा के नाम पर किसी सम्प्रभु देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का मनचाहा अधिकार हासिल कर लिया। प्रस्ताव 1973 पारित होने के तत्काल बाद, 19 मार्च को साम्राज्यवादी गठबंधन ने लीबिया पर हवाई हमला शुरू कर दिया। इस प्रस्ताव के संदर्भ में रूस और चीन की भूमिका का जिक्र करना जरूरी है। इन दोनों ही देशों को वीटो का अधिकार है। यदि वे चाहते तो निष्क्रिय विरोध के बजाय वीटो का प्रयोग करके लीबिया को संकट से बचा सकते थे। लेकिन दोनों ही देश अपनी घरेलू नीतियों के लिए अमरीकी चौधराहट पर निर्भर हैं। वे इस नयी साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था और नाटो गठबन्धन को चुनौती देने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हालात ऐसे ही नहीं बने रहेंगे। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण कोरिया) के सान्या सम्मेलन का वक्तव्य इसी ओर संकेत कर रहा है।

आखिर यह 'विमान वर्जित क्षेत्र' क्या बला है? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमरीकी चौधराहट वाले उद्धत साम्राज्यवादी खेमे द्वारा ईजाद किया गया यह हथकण्डा संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्तरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जी उड़ाते हुए किसी भी देश पर वहाँ के नागरिकों की रक्षा के बहाने युद्ध थोपने और नागरिकों का कत्लेआम करने का एक जरिया है। अपने स्वार्थों के लिए तानाशाही को प्रश्रय देने वाला अमरीका भला किसी देश की जनता को तानाशाही से निजात दिला सकता है? जनक्रान्तियों का इतिहास गवाह है कि जनता अपने दम पर तानाशाहों से निपटती रहती है। अमरीका के लिए 'विमान वर्जित क्षेत्र' अपने साम्राज्यवादी मन्सूबों को पूरा करने का एक बहाना है। इराक और अफगानिस्तान में वह आज तक यही कर रहा है लोकतंत्र की बहाली के नाम पर वहाँ के निर्दोष और निहत्थे लोगों का कत्लेआम। जब श्रीलंका सरकार जाफना में लिट्ठे के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही थी, तब सुरक्षा परिषद कहाँ था? गाजा पट्टी में दो साल पहले जब

इजराइली सेना ने 1400 लोगों की जान ली और 'विमान वर्जित क्षेत्र' की माँग उठी तो 'मानवीय हस्तक्षेप' के अलमबरदार कहाँ थे?

सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित करवाकर नाटो के युद्ध अपराधियों ने उसे लीबिया पर क्रूज मिसाइलों और प्रिडेटर ड्रोन से हवाई हमला और बमबारी में बदल दिया। मौत के इन सौदागरों का मकसद वहाँ नागरिकों की हिफाजत करना नहीं, बल्कि लीबिया के सैनिक ठिकानों को ध्वस्त करना और निहत्थे नागरिकों की हत्या करना है ताकि साम्राज्यवादी समूह गद्दाफी को सत्ता से हटाकर लीबिया पर कब्जा जमा सके। इस घिनौने मंसूबे को पूरा करने के लिए नाटो सेना गद्दाफी और उनके परिवार को सीधे निशाना बना रही है। 30 अप्रैल को त्रिपोली के निकट उनके आवास पर हमला करके नाटो ने उनके छोटे बेटे और तीन पोते-पोतियों की हत्या कर दी। साम्राज्यवादियों के लिए उनका निकृष्ट स्वार्थ ही सब कुछ होता है। फिदेल कास्त्रो ने अपनी टिप्पणी में विस्तार से बताया है कि साम्राज्यवादी देशों के नेताओं के गद्दाफी के साथ कितने मधुर सम्बन्ध थे। आज वे सब के सब उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं।

नाटो द्वारा लगातार बमबारी के बीच मई के उत्तरार्द्ध में अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गद्दाफी, उनके बेटे और लीबिया के गुप्तचर प्रमुख के खिलाफ गिरफ्तारी वारण्ट जारी करने की अपील की। अन्तरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक बिना उकसावे के युद्ध थोपना सबसे जघन्य युद्ध अपराध है। क्या इस कानून के तहत अमरीका, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं के खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए जिन्होंने लीबिया पर गैर-कानूनी तरीके से युद्ध थोपा है? क्या अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश पर युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए जिसने इराक पर कब्जे के लिए बर्बर हमला किया, जिसके चलते 6,50,000 इराकी नागरिक औरतें, बच्चे और बूढ़े तक मारे गये? दरअसल साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनायी गयी इन अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं को आज अरब जगत, अफ्रीकी देशों में नये तरह की औपनिवेशिक व्यवस्था कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि साम्राज्यवादी वहाँ विपुल प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा जमा सकें।

नाटो गठबन्धन ने जनसंहारक हथियारों और अपने पिट्ठुओं के जरिये लीबिया के तेल बहुल पूर्वी क्षेत्र पर एक हद तक नियन्त्रण कर लिया है और देश को विभाजन और बिखराव की ओर धकेल दिया है। अब वे गद्दाफी को धमकी दे

रहे हैं कि यदि उन्होंने देश नहीं छोड़ा तो उनका भी वही हश्र होगा जो स्लोनोदान मिलोशेविक का हुआ था। उल्लेखनीय है कि मिलोशेविक ने युगोस्लाविया से भागने के बजाय नाटो का मुकाबला किया था। अन्ततः साम्राज्यवादियों ने युगोस्लाविया को तहस-नहस कर दिया और मिलोशेविक को कैद कर लिया जहाँ जेल में ही उनकी मौत हो गयी। गद्दाफी ने तय किया है कि वे अपना वतन छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि साम्राज्यवादियों से अन्तिम साँस तक लड़ते हुए मरना पसन्द करेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो फिदेल के शब्दों में "वे अरब राष्ट्रों की एक महान विभूति के रूप में इतिहास में शामिल होंगे" और "...नाटो और उसकी आपराधिक योजना शर्म के कीचड़ में धँस जायेगी।"

अरब जगत के तानाशाहों के खिलाफ जनता की बगावतों का कारण लोकतंत्र के अभाव के साथ-साथ उन समाजों में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी और निजीकरण-उदारीकरण के कारण सार्वजनिक सेवाओं से जनता को वंचित किया जाना था। दुनिया भर में अनाज की कीमतों में भारी वृद्धि ने जनता के आक्रोश को काफी तीव्र कर दिया था। इसके पीछे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा अनाज के व्यापार पर कब्जा करके, कालाबाजारी और सट्टेबाजी को बढ़ावा देना तो था ही, अमरीका द्वारा अनाज से बायोडीजल बनाने पर जोर देने के चलते खाद्यान्न की आपूर्ति में कमी भी एक प्रमुख कारण था। जाहिर है कि जनता साम्राज्यवादियों और उनके देशी संघातियों, दोनों के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रही थी। वह अपनी सभी समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए संघर्षरत थी। लोकतंत्र उनके लिए साधन था, साध्य नहीं। लेकिन स्वतःस्फूर्त और असंगठित आंदोलनों के दम पर देशी-विदेशी लुटेरों से निर्णायक लड़ाई लड़ पाना काफी कठिन था। साम्राज्यवादियों ने जनान्दोलनों की इन्हीं सीमाओं का लाभ उठाते हुए उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की माँग तक सीमित करते हुए बगावत की लहरों को अपने स्वार्थों की ओर मोड़ लिया। अब वे पूरे अरब जगत में सत्ता परिवर्तन करके उसे नई साम्राज्यवादी आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप ढालने और अपने मनचाहे लोगों को शासन सौंपने के लिए हाथ-पाँव मार रहे हैं।

लेकिन दुनिया साम्राज्यवादियों की मर्जी से नहीं चलती, खासतौर पर विश्व जनगण आज चेतना के जिस उन्नत धरातल पर जी रहा है, वहाँ साम्राज्यवादी मंसूबों का पूरा होना आसान नहीं है। इराक और अफगानिस्तान का कत्लो-गारत, तीन हजार अरब डॉलर और सैकड़ों सैनिकों की कुर्बानी के बावजूद अमरीका वहाँ के संसाधनों पर पकड़ बनाने में नाकाम रहा है। लीबिया में साम्राज्यवादियों का

मुकाबला उमर मुख्तार के वारिशों से है, जिनका नाम सुनकर मुसोलिनी की नींद हराम हो जाती थी। अरब और अफ्रीकी जनता में जिस तेजी के साथ साम्राज्यवाद के खिलाफ नफरत और गुस्सा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए साम्राज्यवादी मंसूबों का रेगिस्तान और तेल के समन्दर में गर्क होना कोई हैरत की बात नहीं होगी।

■

इधर न देखो

इधर न देखो
कि जो बहादुर
कलम के या तेग के धनी थे
जो अजमों[1] हिम्मत के मुद्दई[2] थे
अब उनके हाथों में
सिदको-ईमाँ की आजमूदा पुरानी तलवार मुड़ गई है।
इधर न देखो
जो कजकुलह साहबे-हशम[3] थे
जो अहले-दस्तारे-मुहतरम[4] थे
हविस के पुरपेच रास्तों में
कुलह किसी ने गिर्वी रख दी
किसी ने दस्तार बेच दी है
उधर भी देखो
जो अपने रखशाँ लहू के दिनार
मुफ्त बाजार में लुटाकर
लदह[5] में इस वक्त तक गनी[6] हैं
उधर भी देखो
जो हर्फे-हक की सलीब पर अपना तन सजाकर
जहाँ से ओझल हुए
और अहले-जहाँ में इस वक्त तक नबी[7] हैं।

फैज अहमद फ़ैज

1. निश्चय 2. दावेदार 3. ताजदार और शासक 4. प्रतिष्ठा की पगड़ी पहनने योग्य 5. कब्र 6. सम्पन्न 7. पैगम्बर

लीबिया पर कब्जा करने का मंसूबा

21 फरवरी, 2010

पूँजीवादी व्यवस्था का स्वभाव उस संस्थागत ढाँचे पर निर्भर करता है जो उसे ढालता और सँभालता है।

विराट यांकी (अमरीकी) बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए तेल एक प्रमुख सम्पत्ति है। इस ऊर्जा स्रोत के मार्फत उन्हें एक ऐसा औजार मिल गया जिसने पूरी दुनिया में उनकी राजनीतिक शक्ति का अच्छा-खासा विस्तार किया। यही उनका असली हथियार था जब हमारे देश में ज्यों ही पहला न्यायपूर्ण और प्रभुसत्ता-सम्पन्न कानून पारित हुआ, त्यों ही उन्होंने क्यूबा की क्रान्ति को आसानी से खत्म करने का फैसला किया इसे तेल से वंचित कर दो।

इसी ऊर्जा स्रोत पर आज की सभ्यता विकसित हुई। वेनेजुएला इस गोलार्द्ध का एक ऐसा राष्ट्र है जिसने इसकी सबसे भारी कीमत चुकायी। प्रकृति माता ने हमारे इस सहोदर देश को जो विराट तेल-क्षेत्र प्रदान किया था, संयुक्त राज्य अमरीका उसका स्वामी और नियंता बन बैठा।

दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति पर इसने ईरान और साथ ही उसके आस-पास बसे सऊदी अरब, इराक और अरब देशों के तेल क्षेत्रों से अधिकाधिक मात्रा में तेल का दोहन शुरू किया। ये देश प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गये। दुनिया की तेल खपत बढ़ते-बढ़ते लगभग 8 करोड़ बैरल प्रतिदिन के विस्मयकारी आँकड़े तक पहुँच गयी जिसमें अमरीका की अपनी धरती से निकाला गया तेल भी शामिल है और आगे चलकर इसमें गैस, पनबिजली और नाभिकीय ऊर्जा भी शामिल हो गयी। बीसवीं सदी की शुरुआत तक कोयला ही ऊर्जा का बुनियादी स्रोत था जिसने औद्योगिक विकास को सम्भव बनाया। तरल ईंधन से चलने वाले करोड़ों ऑटोमोबाइल और

इंजन तो काफी बाद में तैयार किये गये।

तेल और गैस की फिजूलखर्ची से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी त्रासदी आज मानवता को झेलनी पड़ रही है जिसका रत्ती-भर भी समाधान नहीं हुआ, वह है जलवायु परिवर्तन।

जब हमारी क्रान्ति का उदय हुआ था, उस समय अलजीरिया, लीबिया और मिस्र अभी तेल उत्पादक देश नहीं थे तथा सऊदी अरब, इराक, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के विपुल तेल भंडारों की खोज भी नहीं हुई थी।

दिसम्बर 1951 में लीबिया दूसरे महायुद्ध के बाद आजादी हासिल करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। वही धरती जर्मनी और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच महत्त्वपूर्ण लड़ाईयों की रणभूमि थी जो जनरल इरविन रोमेल और बर्नार्ड मोण्टगोमरी को ख्याति और गौरव प्रदान कर रही थी।

वहाँ पंचानबे फीसदी इलाका पूरी तरह रेगिस्तान है। तकनोलॉजी ने वहाँ बेहतरीन किस्म के बारीक तेल के अक्षय भंडार की खोज में मदद पहुँचायी जिसका उत्पादन आज आठ लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुँच गया जबकि वहाँ प्राकृतिक गैस का भी प्रचुर भंडार मौजूद है। इस समृद्धि के बल पर आज लीबिया की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष की उम्र तक पहुँच गयी है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह अफ्रीकी देशों में सबसे ऊपर है। इसके रूखे रेगिस्तान के नीचे जीवाश्म जल की एक बहुत बड़ी झील है जो क्यूबा के भू-भाग से तिगुनी है। इसी के चलते उस देश के एक छोर से दूसरे छोर तक साफ पानी के पाइप लाइन का जाल बिछाना सम्भव हो पाया।

जब लीबिया आजाद हुआ था तो उसकी आबादी लगभग 10 लाख थी जो आज 60 लाख से भी ज्यादा है।

वर्ष 1969 के सितम्बर महीने में लीबिया की क्रान्ति सम्पन्न हुई। इसके प्रमुख नेता मुअम्मर अल-गद्दाफी, बेदोइन मूल के एक सैनिक थे जो अपने शुरूआती दिनों में मिस्र के नेता गमाल अब्दुल नासिर से प्रेरित हुए थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनके कई निर्णयों का सम्बन्ध उस दौर के ऐसे बदलावों से था जो मिस्र की तरह लीबिया में भी एक कमजोर और भ्रष्ट राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का परिणाम थे।

उस देश के निवासी काफी पुरानी योद्धा परम्परा के वारिश हैं। कहा जाता है कि प्राचीन लीबियाई लड़ाके हैनीबल सेना के एक अंग थे। अपने इन्हीं सैनिकों के

साथ जिन्होंने आल्पस पहाड़ को पार किया था, वह प्राचीन रोम को तबाह करने के करीब था।

कोई व्यक्ति गद्दाफी से सहमत हो सकता है या असहमत। दुनिया भर में खास कर जनसंचार माध्यमों के जरिये सभी तरह की खबरों की घुसपैठ हो रही है। लीबिया में अफरातफरी के बीच जो तरह-तरह की मिली-जुली घटनाएँ हुई हैं, उनमें क्या सच है और क्या झूठ, इसकी ठीक-ठीक जानकारी के लिए किसी व्यक्ति को लम्बे समय तक इन्तजार करना होगा। हमारे लिए, यह चीज एकदम साफ है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार लीबिया में शान्ति को लेकर कतई परेशान नहीं है और नाटो को इस समृद्ध देश पर आक्रमण करने का आदेश देने से हिचकेगी नहीं, शायद यह कुछ घण्टों या कुछ एक दिनों की बात है।

विश्वासघाती इरादों वाले लोगों ने एक झूठ गढ़ लिया है कि गद्दाफी वेनेजुएला की ओर चल चुके हैं, जैसा कि उन्होंने कल दोपहर, रविवार, 20 फरवरी को व्यक्त किया। लेकिन आज उन्हें विदेश मंत्री निकोलस मदुरो से उसका सही जवाब मिल गया जब उसने शब्दशः कहा कि ''वह चाहता है कि लीबियाई जनता बिना साम्राज्यवादी हस्तक्षेप के अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग करते हुए अपनी कठिनाइयों का शान्तिपूर्ण समाधान हासिल करे, जो लीबियाई जनता और राष्ट्र की एकता को बचायेगा...।''

इस बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि लीबियाई नेता पर जो जिम्मेदारियाँ आरोपित की गयी हैं, चाहे वे पूर्णतः या अंशतः झूठी ही क्यों न हों, उनसे मुँह चुराते हुए वे अपने देश का परित्याग करेंगे।

एक ईमानदार व्यक्ति दुनिया की किसी भी जनता के प्रति किये जाने वाले अन्याय के खिलाफ होगा और इस वक्त जनता के खिलाफ नाटो जिस अपराध की तैयारी कर रहा है उसे देखते हुए चुप रहना सबसे बुरी बात होगी।

इस युद्ध-सौदागर संस्था के नेतृत्व का ऐसा करना तय है। हमें निश्चय ही इसकी भर्त्सना करनी चाहिए!

मानवद्रोही मौत का तांडव

23 फरवरी, 2011

मध्य-पूर्व में संयुक्त राज्य अमरीका और उसके नाटो संघातियों द्वारा थोपी गयी लूट की नीति संकट में पड़ गयी है। अनाज की ऊँची कीमतों ने अपरिहार्य रूप से इसको उकसा दिया है। इसका प्रभाव अरब देशों में बहुत ही तीक्ष्ण रूप से महसूस किया जा सकता है जहाँ तेल के विराट स्रोतों के बावजूद एक तरफ पानी की कमी, रेगिस्तान से घिरे इलाके और जनता की आम गरीबी है, तो दूसरी तरफ विशेष सुविधा-प्राप्त तबके द्वारा नियन्त्रित तेल से प्राप्त प्रचुर संसाधन हैं।

अनाज के दाम तीन गुने हो गये, जबकि स्थावर सम्पत्ति की कीमत बढ़ने से मुट्ठीभर अभिजातों के खजाने में करोड़ों-करोड़ डॉलर इकट्ठा हो गये।

अपनी तहजीब और अकीदत में अधिकतर मुस्लिम, अरब जगत ने खुद को तब और अधिक अपमानित महसूस किया जब सरकार ने उनके ऊपर रक्तपात और गोलाबारी शुरू की। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सरकारों का असमर्थ होना तो उनकी उत्पत्ति में ही निहित था क्योंकि वे दूसरे महायुद्ध के अन्त से पहले तक वहाँ मौजूद औपनिवेशिक व्यवस्था की पैदाइश थे और महायुद्ध में विजयी शक्तियों ने उसी के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ को जन्म दिया था और विश्व व्यापार व अर्थव्यवस्था उन देशों पर थोप दी थी।

कैम्प डेविड में अनवर अल-सादात द्वारा दगाबाजी किये जाने के चलते, नवम्बर 1947 की संयुक्त राष्ट्र सन्धि के बावजूद फिलीस्तीनी राज्य अस्तित्व में नहीं आ पाया तथा इजराइल एक मजबूत नाभिकीय शक्ति और अमरीका व नाटो का एक संघाती बन गया।

अमरीकी सैन्य औद्योगिक समूह ने इजराइल को, और साथ ही साथ उन राष्ट्रों

को भी जो इजराइल के आगे झुक गये और उसके द्वारा अपमानित किये जा रहे, हर साल अरबों डॉलर मुहैया कराये हैं।

जिन्न अब बोतल से बाहर निकल गया है और नाटो नहीं जानता कि इसे वश में कैसे करे।

वे लीबिया की अफसोसनाक घटनाओं से ज्यादा लाभ ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोई भी यह नहीं जान सकता कि वहाँ क्या हो रहा है। सभी सूचनाएँ और वृतान्त, यहाँ तक कि जो सबसे विश्वसनीय लगते हों वे भी साम्राज्यवाद द्वारा जनसंचार माध्यमों के जरिये फैलाये जाते रहे हैं, जो अफरातफरी और भ्रामक सूचनाओं को दर्शाते हैं।

विश्व बैंक ने एक लेख में दावे के साथ कहा है कि ''अगर लीबिया और अलजीरिया ने तेल उत्पादन स्थगित कर दिया तो कीमतें अधिकतम 220 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती हैं और कोपेक की निष्क्रिय क्षमता 21 करोड़ प्रति बैरल प्रति दिन तक गिरायी जा सकती है जो खाड़ी युद्ध के दौरान के बराबर है जिसके कारण 2008 में कीमतें 147 डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच गयी थीं।''

इन दिनों इतनी भारी कीमत कौन चुका पायेगा? खाद्य संकट के मौजूदा दौर में इसके नतीजे क्या होंगे? नाटो के सभी नेता तरकीब भिड़ाने में लगे हुए हैं। एएनएसए की सूचना के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कामरान ने कुवैत में भाषण देते हुए यह स्वीकार किया कि ''पश्चिमी देशों की सरकारों ने अरब जगत की अलोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन करके गलती की थी।'' उनकी इस साफगोई पर उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए।

उनके फ्रांसीसी सहकर्मी निकोलस सरकोजी ने कहा ''लीबियाई आम नागरिकों का बड़े पैमाने पर बर्बर और खूनी दमन घृणित है।''

इटली के चान्सलर फ्रांको फ्रात्तिनी ने कहा कि ''त्रिपोली में एक हजार मौत का आँकड़ा विश्वसनीय है...यह त्रासद संख्या एक रक्तपात है।''

हिलेरी क्लिंटन का कहना था ''...'रक्तपात' 'बिलकुल स्वीकार नहीं' है और 'इसे रोकना होगा'...।''

बान की मून ने कहा ''देश में हिंसा का प्रयोग पूरी तरह अस्वीकार्य है।''

''...सुरक्षा परिषद अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के जो भी निर्णय होंगे, उन्हीं के अनुरूप काम करेगी।''

''हम विकल्पों की एक शृंखला पर विचार कर रहे हैं।''

वास्तव में बान की मून जो आशा कर रहे हैं वह यह कि ओबामा निर्णायक शब्द का उच्चारण करें।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने इस बुधवार को दोपहर में ही मुँह खोला और कहा कि जो कदम उठाये जाने हैं उन पर अपने नाटो सहयोगियों से सहमति कायम करने के लिए विदेश मंत्री यूरोप के लिए प्रस्थान करने वाली हैं। कोई भी व्यक्ति धुर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन सिनेटर जॉन मैकन, कनेक्टिकट के सिनेटर, इजराइल समर्थक जोसेफ लिबरमान और टी पार्टी के नेताओं के साथ हुए वाद-विवाद को चाहे तो उनके चेहरे पर पढ़ सकता है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की माँगों पर सुनिश्चित होने के लिए उन्होंने चलाया।

साम्राज्यवादी जन-संचार माध्यमों ने सैनिक कार्रवाई के लिए मैदान तैयार किया है। लीबिया में सैनिक दखलन्दाजी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसके अलावा, इसी की बदौलत यूरोप को प्रतिदिन 20 लाख बैरल हल्के तेल की लगभग गारण्टी हो जायेगी, लेकिन यह तभी हो पायेगा जब लीबिया पर आक्रमण करके गद्दाफी के नेतृत्व को या उनके जीवन को खत्म कर दिया जाये।

बहरहाल, ओबामा की भूमिका कहीं ज्यादा जटिल है। अरब और मुस्लिम जगत की प्रतिक्रिया क्या होगी जब इस उत्पीड़न के परिणामस्वरूप उस देश में भारी मात्रा में खून बहेगा? क्या लीबिया में नाटो की दखलन्दाजी से मिस्र जैसा क्रान्तिकारी ज्वार उठ खड़ा होगा!

इराक में 10 लाख से भी अधिक बेगुनाह अरब नागरिकों का खून बहाया गया, जब झूठे बहानों की आड़ में इस देश पर हमला किया गया। जार्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि अभियान पूरा हुआ।

कोई भी व्यक्ति लीबिया या दुनिया के किसी भी हिस्से के निहत्थे नागरिकों की मौत को सही नहीं ठहरायेगा और मैं चकित हूँ क्या अमरीका और नाटो यही सिद्धान्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उन निहत्थे नागरिकों पर लागू करेंगे जिन्हें मानव रहित ड्रोन बमवर्षक विमान और उनके सैनिक हर रोज कत्ल कर रहे हैं?

यह एक मानवद्रोही मौत का तांडव है।

नाटो का अपरिहार्य युद्ध (भाग-1)

2 मार्च, 2011

लीबिया, मिस्र और ट्यूनीशिया में होने वाली घटनाओं के विपरीत, मानव विकास सूचकांक के मामले में अफ्रीकी देशों के शीर्ष पर है और पूरे महाद्वीप में वहाँ की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वहाँ सरकार विशेष ध्यान देती है। वहाँ के लोगों का सांस्कृतिक स्तर भी निस्संदेह सर्वोत्तम है। वहाँ की समस्याएँ कुछ अलग ही किस्म की हैं। जनता को भोजन और जरूरी सेवाओं की कोई कमी नहीं थी। इस देश को उत्पादन और सामाजिक विकास की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करने के लिए भारी संख्या में विदेशी श्रम-शक्ति की जरूरत थी।

इसी के चलते इसने मिस्र, ट्यूनीशिया और चीन के लाखों मजदूरों को नौकरी दी। इसने धनी देशों के बैंकों में परिवर्तनीय मुद्राओं में अकूत आय और धन जमा किया जिससे उन्होंने उपभोक्ता सामग्री और यहाँ तक कि अत्याधुनिक हथियार भी हासिल किये जो उन्हीं देशों ने मुहैया कराये जो आज मानवाधिकार के नाम पर उस पर हमला करना चाहते हैं।

जन-संचार माध्यमों द्वारा फैलाये गये झूठ के विराट प्रचार के परिणामस्वरूप विश्व जनमत में भारी विभ्रम पैदा हुआ। लीबिया में सचमुच क्या हो रहा है इसकी जानकारी इकट्ठा करने और जो झूठ फैलाये गये हैं उनसे सही तथ्यों को अलग करने में हमें अभी कुछ समय लग सकता है।

टेलीसुर जैसी गम्भीर और प्रतिष्ठित प्रसारण कम्पनियों ने उस समूह के लिए अपने संवाददाताओं और कैमरामैनों को भेजना अपना दायित्व समझा जो युद्ध के विरोधी थे ताकि बता सकें कि वहाँ दरअसल हो क्या रहा है।

संचार व्यवस्था ठप्प कर दी गयी, ईमानदार कूटनीतिक अधिकारी जो दिन-रात निकटवर्ती इलाकों में जाकर वहाँ की गतिविधियों का अवलोकन कर रहे थे, ताकि

जो कुछ हो रहा है उसकी सूचना दे सकें, उनकी जान को खतरा था। साम्राज्यवाद और उसके प्रमुख सहयोगी घटनाओं के बारे में अत्याधुनिक संचार-माध्यम का इस्तेमाल कर रहस्योद्घाटन कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति इस सम्बन्ध में आंशिक रूप से सच्चाई का अनुमान लगाने के लिए भी साम्राज्यवादी स्रोतों पर ही निर्भर था।

इसमें कोई शक नहीं कि बेंगाजी में विरोध-प्रदर्शन कर रहे नौजवान नकाबपोश या बिना नकाब औरतों और मर्दों के चेहरे से सच्चे क्रोध की अभिव्यक्ति हो रही थी।

कोई भी देख सकता है कि इस अरब देश का आदिवासी तबका कितना प्रभावशाली है, बावजूद इसके कि वहाँ की 95 फीसदी जनता ईमानदारी से इस्लाम में विश्वास करती है।

अरब जगत में क्रांतिकारी लहर शुरू होने को लेकर साम्राज्यवाद और नाटो काफी परेशान थे क्योंकि विकसित और धनी देशों की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को टिकाये रखने के लिए जरूरी, तेल का बड़ा भाग वहीं पैदा होता है। वे लीबिया में अन्दरूनी टकराव का लाभ उठाकर वहाँ सैनिक हस्तक्षेप करने से खुद को रोक नहीं पाये। अमरीका ने घटना की शुरूआत के क्षण से ही जो बयान दिये उनका अभिप्राय बिलकुल यही था।

अमरीका के लिए इससे अधिक मंगलकारी अवसर भला क्या होता। नवम्बर के अमरीकी चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के दक्षिणपंथी धड़े ने शब्दजाल फैलाने में माहिर राष्ट्रपति ओबामा पर जबरदस्त प्रहार किया था।

फासीवादी ''अभियान पूरा हुआ'' गुट ने जो आजकल वैचारिक रूप से टी पार्टी के उग्रवादियों द्वारा समर्पित है, वर्तमान राष्ट्रपति को महज एक ऐसी आलंकारिक भूमिका तक सीमित कर दिया है जिसमें उनका स्वास्थ्य कार्यक्रम और संदेहास्पद आर्थिक उद्धार कार्यक्रम भी बजट घाटे के चलते खतरे में थे तथा सार्वजनिक कर्ज में बेलगाम बढ़ोतरी सभी ऐतिहासिक कीर्तिमानों को ध्वस्त करती जा रही थी।

झूठ का अम्बार खड़ा करने और भ्रमजाल फैलाने के बावजूद, अमरीका, लीबिया में सैनिक हस्तक्षेप के लिए सुरक्षा परिषद की मंजूरी के मुद्दे पर चीन और रूसी संघ को अपने पीछे नहीं लगा पाया, जबकि मानवाधिकार परिषद में वह जो उद्देश्य पूरा करवाना चाहता था उस पर उनकी सहमति हासिल कर चुका था। जहाँ तक सैनिक हस्तक्षेप का सवाल है, विदेश मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो बात कही थी,

उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गयी थी ''किसी भी विकल्प को छोड़ा नहीं जा रहा है।''

सही बात यह है कि लीबिया आज गृहयुद्ध में उलझ चुका है, जैसा कि हमारा अनुमान था और संयुक्त राष्ट्र संघ इसे टालने के लिए कुछ नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि उसके महासचिव इस आग में सही मात्रा में घी डालते रहें।

जिस समस्या की सारे खिलाड़ी कल्पना नहीं कर रहे थे, वह यह कि विद्रोह के नेता खुद ही जटिल मामलों पर फूट के शिकार हैं और घोषित कर रहे हैं कि वे सभी तरह के विदेशी सैनिक हस्तक्षेप को अस्वीकार करते हैं।

कई समाचार माध्यमों ने सूचित किया है कि क्रान्ति की समिति के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गोगा ने सोमवार, 28 फरवरी को कहा कि ''लीबिया का बाकी हिस्सा लीबियाई जनता के द्वारा मुक्त किया जायेगा।''

गोगा ने बगावत के दौरान देश के शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली ''राष्ट्रीय परिषद'' के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि ''हम त्रिपोली को मुक्त करने के लिए लीबियाई सेना पर निर्भर हैं।''

''हम खुफिया जानकारी चाहते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपनी सम्प्रभुता को प्रभावित नहीं होने देना चाहते, चाहे हवाई मामले में हो या जमीनी या समुद्री।'' यह बात उसने त्रिपोली से 1000 किमी दूर स्थित एक शहर में पत्रकारों का सामना करते हुए कही।

एएफपी ने पिछले सोमवार को यह खबर प्रेषित की कि ''राष्ट्रीय सम्प्रभुता के मुद्दे पर विरोध करने वाले लोगों की दृढ़ता, बेंगाजी में अन्तरराष्ट्रीय पत्रकारों के सामने कई लीबियाई नागरिकों द्वारा स्वतःस्फूर्त ढंग से व्यक्त किये गये विचारों में प्रतिध्वनित हुई है।''

उसी दिन बेंगाजी विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर अबीर इस्तीना ने कहा ''लीबिया में बहुत ही मजबूत राष्ट्रीय भावना है।''

''इतना ही नहीं, इराक पर हवाई हमले की नजीर समस्त अरब जगत को भ्रमग्रस्त करती है।'' उन्होंने 2003 में अमरीका द्वारा किये गये हमले के सन्दर्भ में इस बात को रेखांकित किया ''जब यह माना गया था कि इससे उस देश में और फिर उसके संक्रमण से पूरे इलाके में लोकतन्त्र आयेगा। यह ऐसी परिकल्पना थी जिसे तथ्यों ने पूरी तरह झुठला दिया।''

प्रोफेसर आगे कहते हैं

''हम जानते हैं कि इराक में क्या हुआ, यही तो कि आज वहाँ पूरी तरह अफरातफरी है और सचमुच हम नहीं चाहते कि उसी राह का अनुगमन किया जाये। हम नहीं चाहते कि गद्दाफी को हटाने की चीख-पुकार मचाते हुए अमरीकी यहाँ आयें।''

लेकिन अबीर इम्तीना के अनुसार ''वहाँ यह भावना भी मौजूद है कि यह हमारी क्रान्ति है, हम लोगों को इसे सम्पन्न करना है।''

इस संवाद के प्रकाशन के कुछ ही घंटों बाद अमरीका के दो अखबारों 'द न्यूयार्क टाइम्स' और 'द वाशिंगटन पोस्ट' ने जल्दी से जल्दी इस विषय की नयी व्याख्या प्रस्तुत की। अगले दिन एक मार्च को डीपीए संवाद संस्था ने इस बारे में सूचित किया ''लीबियाई विपक्ष से अनुरोध कर सकता है कि पश्चिमी देश मुअम्मर अल गद्दाफी के प्रति वफादार सैनिकों पर हवाई रणनीतिक अवस्थिति से बमबारी करें, जैसा कि अमरीकी पत्रकार ने आज सूचना दी है।''

द न्यूयार्क टाइम्स और द वाशिंगटन पोस्ट ने अपने ऑन लाइन संस्करण में उस बात को रेखांकित किया कि ''इस विषय पर लीबियाई क्रान्तिकारी परिषद में विचार-विमर्श हो रहा है।''

द न्यूयार्क टाइम्स की टिप्पणी थी कि इन विचार-विमर्शों से गद्दाफी के दुबारा सत्ता पर कब्जा कर लेने की सम्भावना को देखते हुए विद्रोही नेताओं में बढ़ती निराशा का पता चलता है।

द न्यूयार्क टाइम्स ने परिषद के प्रवक्ता की इस व्याख्या को उद्धृत किया कि ''संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा के अन्तर्गत हवाई हमने की कार्यवाही किये जाने की स्थिति में उसे अन्तरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं माना जायेगा।''

''परिषद में वकील, अकादमिक लोग, न्यायाधीश और लीबियाई-समाज के नामी-गिरामी लोग शामिल थे।''

संवाद कहता है ''द वाशिंगठन पोस्ट ने विद्रोहियों की इस स्वीकृति को उद्धृत किया कि पश्चिमी सहायता के बिना गद्दाफी के प्रति वफादार सैनिकों का मुकाबला करने में काफी समय लग जायेगा और ढेर सारे लोगों की जान जायेगी।''

ध्यान देने योग्य यह है कि इस मामले में एक भी मजदूर, किसान या भवन निर्माता का जिक्र नहीं है, भौतिक उत्पादन में लगे किसी व्यक्ति की या किसी नौजवान, छात्र या प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसी लड़ाके की चर्चा नहीं है। विद्रोहियों को इस रूप में पेश करने की कोशिश क्यों की जा रही है जैसे वे समाज

के जाने माने सदस्य हों जो लीबियाई जनता की हत्या करने के लिए अमरीका और नाटो से बमबारी की माँग कर रहे हों!

किसी न किसी दिन हम बेंगाजी विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर जैसे ही किसी व्यक्ति के माध्यम से सच्चाई जानेंगे जो इतनी वाक्पटुता के साथ उन भयावह अनुभव के बारे में बताती है कि कैसे इराक में लोगों की हत्या की गयी, उनके घर तबाह किये गये, लाखों इराकियों को रोजी-रोटी से मुहताज किया गया या उन्हें निर्वासित होने पर मजबूर किया गया।

आज बुधवार 2 मार्च को ईएफई समाचार सेवा ने एक जानेमाने विद्रोही प्रवक्ता को बयान देते हुए दिखाया जो मेरी राय में सोमवार को दिये गये बयान की एक ही साथ पुष्टि भी करता है और उसका खण्डन भी ''बेंगानी (लीबिया) 2 मार्च। विद्रोही लीबियाई नेता ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् से मुअम्मर अल गद्दाफी शासन के भाड़े के सैनिकों के खिलाफ हवाई हमले की माँग की।

विद्रोहियों के प्रवक्ता अब्दुल हाफिज गोगा ने बेंगाजी में एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया कि ''अपनी रक्षात्मक भूमिका के चलते हमारी सेना भाड़े के सैनिकों पर हमला नहीं कर सकती।''

लीबियाई झड़प के दौरान विदेशी सेना के हस्तक्षेप का हर दम विरोध करने वाले विपक्षी बलों के प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ''रणनीतिक हवाई हमला, विदेशी दखलन्दाजी से भिन्न होता है जिसका हम विरोध करते हैं।''

ढेर सारे साम्राज्यवादी युद्धों में से कौन सा युद्ध इससे मिलता-जुलता लगता है?

वह जो 1936 में स्पेन में हुआ था। 1935 में इथोपिया के खिलाफ मुसोलिनी का युद्ध? 2003 में जार्ज डब्ल्यू बुश का इराक के खिलाफ या लातिन अमरीकी देशों की जनता के खिलाफ संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा किये गये दर्जनों दूसरे युद्ध 1846 में मैक्सिको पर हमले से लेकर 1982 में फॉकलैण्ड द्वीप पर हमले तक?

इसमें बे ऑफ पिग्स पर भाड़े के सैनिकों का हमला, एक घिनौना युद्ध और पिछले 50 वर्षों से लगातार हमारी मातृभूमि की नाकेबन्दी भी शामिल है जिसकी अगली सालगिरह अगले 16 अप्रैल को होगी।

इन सभी युद्धों में वियतनाम युद्ध की तरह ही जिसमें लाखों लोगों को जान गँवानी पड़ी, अत्यन्त मानवद्रोही बहाने और तौर-तरीके अपनाये गये।

लीबिया में होने वाली अपरिहार्य सैनिक दखलन्दाजी के बारे में जिस किसी के मन में थोड़ा भी संदेह हो उनका ध्यान एपी समाचार एजेंसी द्वारा प्रेषित, आज ही प्रकाशित, उस प्रमुख समाचार पर दिलाना चाहूँगा जो मेरी राय में काफी जानकारी देने वाला है ''कूटनीतिज्ञों ने कहा है कि नाटो देश 1990 के दशक में बाल्कन के ऊपर आजमाये गये उड़ान वर्जित क्षेत्र को मॉडल के रूप में अपनाते हुए एक आकस्मिक योजना बना रहे हैं, जो उस वक्त लागू की जायेगी, जब अन्तरराष्ट्रीय समुदाय लीबिया के ऊपर हवाई उड़ान घेराबन्दी थोपने का निर्णय लेगा।''

आगे इसने निष्कर्ष दिया कि ''अधिकारियों ने मामले की नजाकत को देखते हुए अपना नाम बताने से मना किया, यह संकेत दिया कि जिन सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है उनमें 1993 में सुरक्षा परिषद की इजाजत से बोस्निया पर पश्चिमी सैनिक गठजोड़ द्वारा थोपी गयी हवाई उड़ान घेराबन्दी क्षेत्र से लेकर 1999 में कोसोवो पर नाटो द्वारा की गयी बमबारी तक शामिल है, जिसकी इजाजत सुरक्षा परिषद ने नहीं दी थी।''

नाटो का अपरिहार्य युद्ध (भाग-2)

3 मार्च, 2011

गद्दाफी जब 28 वर्ष के थे और लीबियाई सेना में कर्नल थे, तभी उन्होंने अपने सहयोगी, मिस्र के नेता अब्दुल नासिर से प्रेरित होकर 1969 में बादशाह इदरिस को सत्ता से हटा दिया था। इसके बाद ही वहाँ महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी कदम उठाए गये, जैसे भूमि सुधार और तेल का राष्ट्रीयकरण। इससे प्राप्त होने वाली आय को आर्थिक और सामाजिक विकास में, खास तौर पर लीबिया के विस्तृत रेगिस्तानी इलाके में कम सिंचित जमीन पर रहने वाली आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया गया।

''जीवाश्म जल'' का एक विस्तीर्ण और गहरा समुद्र उस रेगिस्तान के नीचे मौजूद था। जब मैंने वहाँ कृषि क्षेत्र में हो रहे एक प्रयोग के बारे में सुना तो मेरे ऊपर इसका काफी असर हुआ और ऐसा लगा कि भविष्य में ये जलाशय तेल से भी अधिक मूल्यवान साबित होंगे।

मुस्लिम राष्ट्रों में इस्लाम धर्म उस मजबूत आदिवासी प्रवृत्ति का प्रतिकार करने में एक हद तक सहायक हुआ जो इस अरब देश में आज तक कायम है।

लीबियाई क्रान्तिकारियों ने कानूनी और राजनीतिक संस्थाओं के सम्बन्ध में खुद अपने क्रान्ति के विचारों की खोज की और उन्हें व्यवहार में उतारा जिसका क्यूबा सिद्धान्ततः आदर करता है।

हमने लीबियाई नेतृत्व की अवधारणाओं को लेकर कोई भी विचार व्यक्त करने से पूरी तरह परहेज किया।

हम साफ-साफ देख सकते हैं कि अमरीका और नाटो की असली चिन्ता लीबिया नहीं है, बल्कि अरब जगत में उत्पन्न क्रान्तिकारी लहर है, जिसे वे हर कीमत पर रोकना चाहते हैं।

इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता कि हाल के वर्षों में मिस्र और ट्यूनीशिया में बगावत उठ खड़ी होने से ठीक पहले तक अमरीका और नाटो सहयोगियों के साथ लीबिया के सम्बन्ध काफी मधुर थे।

लीबिया के साथ उच्च स्तरीय बैठक में शामिल नाटो नेताओं को गद्दाफी से कोई शिकायत नहीं थी। यह देश उनके लिए अच्छे किस्म के तेल, गैस और पोटाशियम की आपूर्ति का सुरक्षित स्रोत था। जो समस्याएँ शुरूआती दशकों में पैदा हुई थीं, उन्हें हल कर लिया गया था।

तेल निकालने और उसकी ढुलाई करने जैसे रणनीतिक क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोल दिए गये थे।

निजीकरण को कई सार्वजनिक उद्यमों तक विस्तारित किया गया था।

अजनार तार्किक रूप से, गद्दाफी की हद से ज्यादा तारीफ करते थे और उनके पीछे ब्लेयर, बर्लुस्कोनी, सरकोजी, जापातेरो और मेरे मित्र, स्पेन के बादशाह ने तो लीबियाई नेता के सम्मान में शर्मनाक तरीके से कवायद की थी। वे सब खुश थे।

हालाँकी ऐसा लग सकता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। मैं तो बस अपने आप से यह पूछ रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या है कि अब वे गद्दाफी को हेग के अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सामने पेश करना चाहते हैं।

वे हर रोज चौबिसों घण्टे यह इल्जाम लगा रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन करने वाले निहत्थे लोगों पर गोली चलायी गयी। वे दुनिया को यह क्यों नहीं बनाते कि लीबिया के पास जो भी हथियार हैं और उससे भी बढ़कर दमन के जो अत्याधुनिक तंत्र हैं, वे सब के सब अमरीका, ब्रिटेन और गद्दाफी के जाने माने मेजबानों ने मुहैया कराये थे।

लीबिया पर हमले की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किये जा रहे मानवद्रोह और झूठ-फरेब का मैं तीव्र विरोध करता हूँ।

अन्तिम बार मैं मई 2001 में गद्दाफी से मिलने गया था, उस घटना के 15 साल बाद जब रीगन ने उनके बहुत ही मामूली से मकान पर हमला किया था, जहाँ ले जाकर उन्होंने हमें दिखाया कि उसकी क्या हालत बना दी गयी थी। उस मकान पर हवाई जहाज से सीधा हमला किया गया था और वह बुरी तरह क्षतीग्रस्त हो गया था। उनकी तीन साल की छोटी बेटी उस हमले में मारी गयी थी। उस बच्ची की हत्या रोनाल्ड रीगन ने की थी। इस हमले के लिए नाटो, मानवाधिकार समिति या सुरक्षा परिषद से पूर्व सहमति नहीं ली गयी थी।

उससे पहले मैं वहाँ 1977 में गया था, लीबिया में क्रान्तिकारी प्रक्रिया शुरू होने के आठ साल बाद। मैंने त्रिपोली का दौरा किया, मैंने शेभा में आम जन सम्मेलन में भाग लिया मैं वहाँ की खेती में पहले-पहल हो रहे प्रयोगों को देखने गया जो जीवाश्म जल के विराट समुद्र से पानी निकाल कर किया जा रहा था। मैं बेंगाजी गया जहाँ मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। यह एक बहुचर्चित देश था जो दूसरे विश्व युद्ध की ऐतिहासिक लड़ाईयों का गवाह रहा था। तब वहाँ आज की तरह 60 लाख की आबादी नहीं थी, न ही उन्हें अपने यहाँ इतनी भारी मात्रा में तेल और जीवाष्म जल होने की जानकारी थी। अफ्रीका में पुर्तगाल के पूर्ववर्ती उपनिवेश पहले ही आजाद हो चुके थे।

हमने अंगोला में अमरीकियों द्वारा आदिवासी पट्टी में एक छोर से दूसरे छोर तक संगठित भाड़े के सैनिकों, मोबुतु सरकार और शस्त्र-सज्जित सुप्रशिक्षित नस्ली, रंगभेदी सेना के खिलाफ 15 सालों तक लड़ाई लड़ी। इस सेना ने जैसा कि अब सब को पता है अमरीकी निर्देश पर 1975 में अंगोला की आबादी को रोकने के लिए अंगोला पर आक्रमण किया और अपनी गाड़ियों से सुसज्जित सैनिकों सहित लुआंडा के बाहरी इलाके तक पहुँच गये। भारी संख्या में क्यूबाई प्रशिक्षक इस नृशंस हमले में मारे गये। जल्दी से जल्दी वहाँ जरूरी संसाधन भेजे गये।

क्यूबाई अन्तरराष्ट्रीयतावादियों और अंगोला के सैनिकों ने नस्लवादियों को उस देश से खदेड़ कर दक्षिण अफ्रीका द्वारा अधिकृत नामीबिया की सरहद तक धकेल दिया। इसके बाद साम्राज्यवादियों ने उन्हें अंगोला में क्रान्तिकारी प्रक्रिया का विनाश करने की जिम्मेदारी सौंपी।

अमरीका और इजराइल के समर्थन से उन्होंने नाभिकीय हथियार विकसित कर लिये। ये हथियार उनके पास तब भी थे जब क्यूबा और अंगोला के सैनिकों ने कुई कुआतावेले में उनकी जमीनी और हवाई सेना को हराया था और नाभिकीय जोखिम का मुकाबला करते हुए, परम्परागत रणकौशल और साधनों का प्रयोग करके वे नामिबिया की सरहद तक बढ़ आये थे जहाँ नस्ली सैनिक प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहे थे। इतिहास में दो बार हमारे सैनिकों पर नाभिकीय हथियारों द्वारा हमला होने का खतरा मंडराया था अक्टूबर 1962 में और दक्षिणी अंगोला में; लेकिन उस दूसरे मौके पर दक्षिण अफ्रीका जिन नाभिकीय हथियारों से लैस था उन्हें मोर्चे पर लगाने के बाबजूद उस पराजय से बच नहीं पाया जिसने वहाँ की घृणित व्यवस्था के अन्त को सुनिश्चित कर दिया। इन सभी घटनाओं को अमरीका में रोनाल्ड रीगन

और दक्षिण अफ्रीका में पीट बोया की सरकार के अधीन अन्जाम दिया गया।

आज इन घटनाओं और साम्राज्यवादी दुस्साहस की कीमत चुकाने वाले हजारों इंसानों की मौत की कहीं कोई चर्चा नहीं है।

आज जब उसी तरह का एक और भारी खतरा अरब जनता के ऊपर मँडरा रहा है, महज इसलिए कि वहाँ के लोगों को लूट और उत्पीड़न का शिकार होते रहना मंजूर नहीं, तो मुझे उन घटनाओं को याद करते हुए काफी अफसोस हो रहा है।

अरब जगत की जिस क्रान्ति से अमरीका और नाटो इतना अधिक भयभीत हैं वह उन लोगों की देन है जो हर तरह के विशेषाधिकारों का गुस्ताखी से दिखावा करते हैं और इसीलिए इसका भवितव्य 1789 की फ्रांसीसी क्रान्ति से कहीं ज्यादा गम्भीर होगा, जिसकी शुरुआत बास्तील के किले पर धावा बोलने के साथ हुई थी।

लुई चौदहवें ने जब यह दावा किया था कि मैं ही राज्य हूँ, तब इतना विशेषाधिकार सम्पन्न नहीं था जितना सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल-अजीज। साथ ही इस रेगिस्तानी देश की सतह के नीचे जो विपुल सम्पदा है उससे कम ही लुई के पास थी। यान्की बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ ही आज वहाँ तेल निकालने और दुनिया भर में उसकी कीमत तय करने का फैसला लेती हैं।

जब लीबियाई संकट शुरू हुआ, तब से सऊदी अरब में तेल का दोहन न्यूनतम मूल्य पर प्रति दिन दस लाख बैरल तक बढ़ गया, परिणामस्वरूप केवल सिद्धान्त रूप में उस देश की और उस पर नियंत्रण रखने वालों की आय बढ़कर एक अरब डालर प्रतिदिन हो गयी।

इससे कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि सऊदी अरब की समूची जनता पैसों में डूब-उतरा रही है। निर्माण मजदूरों और दूसरे क्षेत्रों में तुच्छ मजदूरी पर 13-14 घण्टे रोज काम करने वाले लोगों की रोजमर्रे की जिन्दगी सचमुच दिल दहला देने वाली है।

लूट की मौजूदा व्यवस्था को हिला कर रख देने वाले क्रान्तिकारी उभार से खौफ खाये हुए, मिस्र और ट्यूनीशिया के मजदूरों, जॉर्डन के बेरोजगार नौजवानों, फिलिस्तीन के अधिकृत इलाकों और यहाँ तक कि यमन, बहरीन और प्रति व्यक्ति ऊँची आय वाले अरब अमीरात के लोगों ने भी जिन घटनाओं को अंजाम दिया उससे सऊदी समाज के शीर्षस्थ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए।

पहले के समय से उलट, आज घटनाओं के बारे में अरब जनता को तत्काल सूचना मिल जाती है, चाहे बुरी तरह तोड़-मरोड़ कर ही सही।

विशेषाधिकार युक्त तबके की यथास्थिति के लिए सबसे खराब बात यह है कि एक के बाद एक हो रही इन घटनाओं के साथ-साथ अनाज की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है और जलवायु परिवर्तन का विनाशकारी परिणाम सामने आया है। दूसरी तरफ अमरीका जो दुनियाभर में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके पैदावार का 40 प्रतिशत और सोयाबीन का बड़ा हिस्सा जैव ईंधन पर खर्च कर रहा है, ताकि मोटर गाड़ियों की उदरपूर्ति कर सके।

पारिस्थितिकी और कृषि उत्पादों के विश्व विख्यात विद्वान लेस्टर ब्राउन, निश्चय ही हमें वर्तमान खाद्य संकट की सही जानकारी दे सकते हैं।

बोलिवारियाई राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज लीबिया में नाटो की दखलअन्दाजी के बिना ही कोई समाधान तलाशने का साहसपूर्वक प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की सम्भावना बढ़ जायेगी, यदि वे दखलन्दाजी के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही जनमत तैयार करने का एक व्यापक आन्दोलन खड़ा करने का कमाल हासिल कर सकें और लोगों को इराक के पाशविक अनुभवों को दूसरे किसी देश में दुहराये जाते न देखना पड़े।

नाटो युद्ध, झूठ और व्यापार

9 मार्च, 2011

ढेर सारे लोग जानते हैं कि सितम्बर 1969 में अनोखे चरित्र वाला एक अरब बेदोइन सैनिक, मुअम्मर अल-गद्दाफी ने मिस्री नेता गमाल अब्दुल नासिर के विचारों से प्रेरित होकर सशस्त्र सैनिकों के दिल में लीबिया के बादशाह इदरिस-I की सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक आन्दोलन प्रवर्तित किया। ट्यूनीशिया और मिस्र के बीच उत्तरी अफ्रीका में स्थित लीबिया लगभग पूरी तरह रेगिस्तान से ढका, बहुत ही कम आबादी वाला देश है।

लीबिया के महत्त्वपूर्ण मूल्यवान उर्जा स्रोतों की दिनों-दिन खोज होती जा रही थी।

त्रिपोली इलाके के बंजर रेगिस्तानी चरवाहों के आदिवासी बेदोइन परिवार में जन्मे, गद्दाफी पूरी तरह उपनिवेषवाद विरोधी थे। सबको पता है कि उनके दादा इटली के हमलावरों से लड़ते हुए मारे गये थे जब 1911 में उन लोगों ने लीबिया पर हमला किया था। उपनिवेशवादी शासन और फासीवाद ने वहाँ के हर व्यक्ति की जिन्दगी बदल दी थी। यह भी कहा जाता है कि उनके पिता जो औद्योगिक मजदूर थे, उन्हें जेल में बन्द कर लिया गया था।

गद्दाफी के विरोधी भी बताते हैं कि जब वे छात्र थे, तभी से उनकी तीक्ष्ण बुद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। बादशाह के खिलाफ अपनी गतिविधियों के चलते उन्हें हाई स्कूल से निकाल दिया गया था। किसी तरह उन्होंने किसी दूसरे स्कूल में नाम लिखवाया और आगे चलकर 21 वर्ष की उम्र में बेंगाजी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। फिर उन्होंने बेंगाजी सैनिक कालेज में दाखिला लिया जहाँ उन्होंने आजाद अधिकारियों का गुप्त यूनियन नामक आन्दोलन खड़ा किया।

बाद में ब्रिटिश मिलिट्री अकादमी से अपनी पढ़ाई पूरी की।

इसी पृष्ठभूमि में हम लीबिया में और अन्य राजनीतिक नेताओं पर उनके असाधारण प्रभाव को समझ सकते हैं, चाहे वे लोग आज गद्दाफी के समर्थक हों या न हों।

उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन असंदिग्ध रूप से क्रान्तिकारी घटनाओं के साथ शुरू किया।

मार्च 1970 में विराट राष्ट्रवादी प्रदर्शनों के बाद वे ब्रिटिश सैनिकों से देश को खाली करवाने में कामयाब रहे तथा जून में अमरीका ने त्रिपोली के निकट वायु सेना के विशाल अड्डे को खाली कर दिया और उसे लीबिया के सहयोगी, मिस्र के प्रशिक्षकों को सौंप दिया।

1970 में विदेशी पूँजी की हिस्सेदारी वाली कई पश्चिमी तेल कम्पनियाँ और बैंकिंग कम्पनियाँ क्रान्ति से बुरी तरह प्रभावित हुईं। 1971 के अन्त में कुख्यात ब्रिटिश पेट्रोलियम का भी यही हश्र हुआ। कृषि क्षेत्र में सभी इटालियन सम्पत्तियों को जब्त कर लिया गया तथा उपनिवेशवादियों और उनके वंशजों को लीबिया से बाहर खदेड़ दिया गया।

विराट कम्पनियों का नियन्त्रण राज्य के हस्तक्षेप से निर्देशित होता था। उस देश में उत्पादन का स्तर पूरे अरब जगत में सबसे ऊँचा था। जुआ खेलना और शराब पीना वर्जित था। महिलाओं की परम्परागत रूप से सीमित कानूनी स्थिति को बेहतर बनाया गया था।

लीबियाई नेता क्रान्तिवादी सिद्धान्तों में लिप्त हो गये थे जो साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों के विरुद्ध था। यही वह मंजिल थी जब गद्दाफी ने खुद को एक ऐसी चीज के बारे में सिद्धान्त निरुपण के लिए समर्पित किया जिसकी इस विश्लेषण में कोई जगह नहीं थी सिवाय इसके कि 1969 के संवैधानिक घोषणा के पहले अनुच्छेद में महान समाजवादी लीबियाई जम्हीरिया के ''समाजवादी'' चरित्र को रेखांकित किया गया था।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि अमरीका और उसके सहयोगी देशों की मानवाधिकार में कभी भी रुचि नहीं रही है।

सुरक्षा परिषद में जो बर्रे का छत्ता बन रहा है, जैसा कि जेनेवा मुख्यालय पर मानवाधिकार परिषद की बैठक के समय न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान हुआ, वह शुद्ध नौटंकीबाजी है।

मैं राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह समझता हूँ, जो इतने सारे अन्तर्विरोधों और नपुंसक बहसों में उलझे हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्वार्थों और समस्याओं के उलझे हुए जाले की हिफाजत करनी है।

हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वार्थी सदस्यों का चरित्र, उनका वीटो का अधिकार तथा नाभिकीय हथियारों और कुछ दूसरी संस्थाओं पर उनका कब्जा ही मानव जाति के ऊपर अपने विशेषाधिकारों और स्वार्थों को थोपने के मूल कारण हैं। उनमें से ढेर सारे मुद्दों पर कोई सहमत हो या न हो, लेकिन कोई भी उन्हें उचित और नैतिक साधन नहीं मान सकता।

साम्राज्यवाद अब घटनाओं को गद्दाफी के इर्द-गिर्द घूमते हुए देखना-दिखाना चाहता है चाहे वे उसके लिए जिम्मेदार हों या न हों, क्योंकि लीबिया में सैनिक हस्तक्षेप करना और अरब जगत में क्रान्तिकारी लहरों के उभार को आघात पहुँचाना उसकी जरूरत है। अब से पहले उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था वे अपना मुँह बन्द किये रहे और अपना कारोबार जारी रखा।

गुप्त लीबियाई विद्रोह जिसे यांकी गुप्तचरों और गद्दाफी की अपनी गलतियों के द्वारा प्रोत्साहन मिल रहा है, उसके सम्बन्ध में यह महत्त्वपूर्ण है कि जनता अपने साथ धोखेबाजी नहीं होने देना चाहती, क्योंकि बहुत जल्दी ही विश्व जनमत को पर्याप्त तथ्यों की जानकारी मिल जायेगी जिसके आधार पर वह तय कर सके कि उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है।

मेरी राय में जिसे मैं घटना की शुरूआत के समय से ही कहता रहा कि हमें नाटों के युद्ध सौदागरों की योजना की भर्त्सना करनी चाहिए।

तीसरी दुनिया के कई देशों की तरह लीबिया भी गुट निरपेक्ष आन्दोलन, 77 का समूह और अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, जिनके माध्यम से इसकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के साथ अलग-अलग सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं।

संक्षिप्त रूप में क्यूबा में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धान्तों और मार्ती के विचारों से प्रेरित होकर 1956 में क्रान्ति सफल हुई। अमरीका से हम 90 मील की दूरी पर हैं जिसने हमारे देश पर प्लाट अमेंडमेन्ट थोप रखा था और हमारी अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर लिया था।

क्रान्ति के तुरन्त बाद, साम्राज्यवाद ने हमारी जनता के खिलाफ आपराधिक आर्थिक नाकेबन्दी, घिनौने युद्ध, क्रान्ति विरोधी गिरोहों और भाड़े के सैनिकों द्वारा

'बे ऑफ पिग' पर हमलों को बढ़ावा दिया। वह एक विमान वाहक पोत से इन कार्रवाइयों की निगरानी करता रहा और उसके नौसैनिक इस बात के लिए हमेशा तैयार रहे कि भाड़े के सैनिकों को निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होते ही वे हमारी धरती पर उतर पड़ें।

ठीक डेढ़ साल बाद उन्होंने अपने नाभिकीय शस्त्रागार के बल पर हमें धमकाया। नाभिकीय युद्ध किसी भी क्षण शुरू हो सकता था।

मैक्सिको को छोड़कर सभी लातिन अमरीकी देशों ने आपराधिक नाकेबंदी में हिस्सा लिया जो आज भी जारी है, लेकिन हमारे देश ने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन लोगों को यह बात याद दिलाना जरूरी है जिनकी इतिहास की याद्दास्त कमजोर है।

जनवरी 1986 में, इस कल्पना का सहारा लेते हुए कि तथाकथित क्रान्तिकारी आतंकवाद के पीछे लीबिया का हाथ है, रीगन ने उस देश के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक सम्बन्ध तोड़ लेने का आदेश दिया।

मार्च में सिदरा की खाड़ी से, जो लीबियाई राष्ट्रीय समुद्री सीमा के अर्न्तगत आता है, विमान वाहक पोतों ने लीबिया पर हमला किया जिसमें सोवियत रूस से प्राप्त मिसाइल लॉन्चर और तटीय रडार प्रणाली से लैस उसकी कई नौसैनिक इकाइयाँ तबाह हो गयीं।

5 अप्रैल को बर्लिन का एक डिस्को और उसमें नाचने गये अमरीकी सैनिक प्लास्टिक विस्फोट के शिकार हो गये। तीन लोग मारे गये जिसमें दो अमरीकी सैनिक थे और कई लोग घायल हुए।

रीगन ने गद्दाफी पर इल्जाम लगाया और अपनी वायु सेना को इसका बदला लेने का आदेश दिया। छठे बेड़े के विमान वाहक और ब्रिटेन के सैनिक अड्डों से तीन स्क्वाड्रनों ने उड़ान भरी तथा त्रिपोली और बैंगाजी के सात सैनिक लक्ष्यों पर मिसाइलों और बमों से हमला किया।

40 लोग मारे गये जिनमें से 15 नागरिक थे। बमबारी करने वालों के हमलों से सचेत होकर गद्दाफी ने अपने परिवार को एक जगह इकट्ठा किया और बेब अल अजीजिया के सैनिक ठिकाने के पास अपने निवास को खाली करके वे राजधानी के दक्षिण में जा रहे थे। अभी घर खाली करने का काम चल ही रहा था कि एक मिसाइल ने सीधे उनके आवास पर हमला किया। उनकी छोटी बेटी हान्ना मारी गयी और दो अन्य बच्चे जख्मी हो गये। इस घटना की व्यापक रूप से भर्त्सना की गयी।

संयुक्त राष्ट्र संघ एसेम्बली ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्तरराष्ट्रीय कानून की इस अवहेलना की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। गुट निरपेक्ष आन्दोलन, अरब लीग और ओएयू ने भी कड़े शब्दों में निन्दा प्रस्ताव पारित किया।

21 दिसम्बर 1988 को लन्दन से न्यूयार्क जा रहा 747 पैन एम बोइंग विमान एक बम विस्फोट होने के चलते बीच हवा में विखंडित हो गया। विमान के अवशेष लौकरबी के ऊपर गिरे और इस त्रासदी में 21 राष्ट्रों के 27 लोग मारे गये।

पहले अमरीका को शक हुआ कि यह ईरान द्वारा की गयी बदले की कार्रवाई है जिसके सरकारी एयरलाइन के एक एयर बस में जा रहे 200 नागरिकों को मार दिया गया था। यान्किायों के मुताबिक जाँच एजेन्सियों ने दो लीबियाई गुप्तचरों को इसमें लिप्त पाया था। लीबिया पर ऐसा ही आरोप फ्रांसीसी एयरलाइन की ब्राजविले से पेरिस जा रहे विमान के दुर्घटना-ग्रस्त होने पर भी लगाया गया था। इसमें लीबिया के दो अधिकारियों को आरोपित किया गया था जिनका प्रत्यर्पण करने से गद्दाफी ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने इस सच्चाई से पूरी तरह इनकार कर दिया।

उनके खिलाफ ऐसे ही मनगढंत और अनर्थकारी आरोप रीगन और जॉर्ज बुश सीनियर ने मिलजुल कर गढ़े।

1975 से लेकर रीगन सरकार के अन्तिम दिनों तक क्यूबा ने अंगोला और अन्य अफ्रीकी देशों में अपने अन्तरराष्ट्रीय कर्त्तव्य के प्रति खुद को समर्पित किया था। हम लीबिया और उसके आसपास विकसित हो रहे टकराव के प्रति सचेत थे क्योंकि पठनीय सामग्री और चश्मदीदों के विवरण जो उस देश या अरब जगत के साथ करीब से जुड़े लोगों ने लिखे थे, हमारे पास उपलब्ध थे। साथ ही, इसलिए भी कि विभिन्न देशों के तरह-तरह के व्यक्तियों के बारे में हमारे अनुभव थे जिनके साथ हम उन वर्षों के दौरान सम्पर्क में रह चुके थे।

कई जाने-माने अफ्रीकी नेताओं ने, जिनके साथ गद्दाफी के नजदीकी सम्बन्ध थे, लीबिया और ब्रिटेन के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों का हल करने का प्रयास किया।

सुरक्षा परिषद ने लीबिया पर जो प्रतिबन्ध लगाये थे, उसे उठा लिया जाना तय था क्योंकि गद्दाफी ने विमान को मार गिराने के आरोपी दोनों लोगों को कुछ शर्तों के साथ स्कॉटलैण्ड में मुकदमा चलाने के लिए समर्पित करना स्वीकार कर लिया था।

अन्तर-यूरोपीय बैठकों में लीबियाई प्रतिनिधियों को बुलाया जाना शुरू हो

गया। जुलाई 1999 में लन्दन ने कुछ अतिरिक्त रिआयतें देते हुए लीबिया के साथ पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करना शुरू किया।

उसी साल सितम्बर में यूरोपीय यूनियन के मंत्रियों ने 1992 में वाणिज्य से सम्बन्धित प्रतिबन्ध के जो कदम उठाये गये थे, उन्हें वापस लेना स्वीकार किया था।

2 दिसम्बर को इटली के प्रधानमंत्री मसीमो द अलेमा किसी यूरोपीय सरकार के पहले शीर्ष व्यक्ति थे जिन्होंने लीबिया का दौरा किया।

सोवियत संघ और यूरोपीय समाजवादी खेमे के बिखराव के बाद गद्दाफी ने अमरीका और नाटो की माँगों को मान लेने का फैसला किया।

जब मैंने 2001 में लीबिया का दौरा किया तो गद्दाफी ने हमें उस विश्वासघाती हमले के ध्वंसावशेष दिखाये जिसमें रीगन ने उनकी बेटी का कत्ल किया था और जब उनके पूरे परिवार का खात्मा होने वाला था।

2002 की शुरूआत में अमरीकी विदेश मंत्रालय ने सूचित किया कि उनके और लीबिया के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है।

मई में लीबिया को आतंकवाद की सहायता करने वाली सरकारों की सूची में शामिल कर दिया गया, बावजूद इसके कि ''बुराई की धुरी'' के बारे में अपने कुख्यात भाषण में जार्ज डब्ल्यू बुश ने इस अफ्रीकी देश का नाम नहीं लिया था।

2003 शुरू होते ही, लीबिया के साथ ब्रिटेन और फ्रांस की मुआवजे को लेकर आर्थिक सहमति बन जाने के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया के खिलाफ 1992 में लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया।

2003 के अन्त होते-होते, बुश और टोनी ब्लेयर ने लीबिया के साथ एक समझौते की सूचना दी, जिसने ब्रिटेन और अमरीका को गुप्तचर विशेषज्ञों द्वारा गैर-परम्परागत हथियार कार्यक्रमों के बारे में एकत्रित दस्तावेज सौंपे थे। इनमें 300 किमी से भी अधिक दूरी तक मार करने वाले बेलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। इन दोनों देशों के अधिकारियों ने पहले ही विभिन्न ठिकानों का दौरा कर लिया था। बुश ने खुद बताया था कि यह त्रिपोली और वाशिंगटन के बीच कई महीनों की बातचीत का नतीजा था।

गद्दाफी ने निरस्त्रीकरण के अपने वायदे पूरे कर दिये। कुछ ही महीनों में लीबिया ने 800 किमी तक मार करने वाली स्कड-सी की पाँच इकाइयाँ और 300 किमी से अधिक मार करने वाली छोटी दूरी की सैकड़ों, सुरक्षात्मक मिसाइलें उनके हवाले कर दी।

2002 के अक्टूबर से त्रिपोली के लिए लम्बी दौड़ शुरू हुई 2003 में जोस मारिया अजनार, 2004 के फरवरी अगस्त और अक्टूबर में वर्लुस्कोनी, 2004 के मार्च में ब्लेयर, उसी साल अक्टूबर में जर्मनी के स्रोडर, 2004 के नवम्बर में जाक शिराक। हर व्यक्ति प्रसन्न था। श्रीमान पैसा एक शक्तिशाली भद्र पुरुष है।

गद्दाफी ने विजयोल्लास के साथ यूरोप का भ्रमण किया। अप्रैल 2004 में यूरोपीय उद्योग के अध्यक्ष रोमानो प्रोदी ने ब्रूसल्स में उनकी आगवानी की। उसी साल अगस्त में लीबियाई नेता ने बुश को अपने देश की यात्रा के लिए आमन्त्रित किया। एकॉन मोबिल, शैवेरॉन टेक्साको और कोनोको फिलिप्स ने संयुक्त उपक्रम के माध्यम से कच्चा तेल निकालने का कारोबार फिर स्थापित करने का फैसला लिया।

मई 2006 में अमरीका ने लीबिया को आतंकवादी देशों की सूची से हटाने और पूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की।

2006 और 2007 में फ्रांस और अमरीका ने शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय सहयोग समझौते पर दस्तखत किये। 2007 में ब्लेयर ने एक बार फिर सिदरा में गद्दाफी से मुलाकात की। बी पी ने एक बयान में बताया कि उसने गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए एक ''अत्यन्त महत्त्वपूर्ण'' समझौते पर हस्ताक्षर किया।

दिसम्बर 2007 में गद्दाफी ने फ्रांस के दो दौरे किये और कुल 10 अरब यूरो के नागरिक और सैनिक उपकरणों के लिए करार किये। स्पेन का दौरा करके वे राष्ट्रपति जोस लूई रोड्रिगज जापतेरो से मिले। महत्त्वपूर्ण नाटो देशों के साथ लाखों डॉलर के करार किये गये।

आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमरीका और नाटो देश इतनी हड़बड़ी में अपने दूतावास खाली करने पर आमदा हो गये।

यह बहुत ही अनोखा है।

महत्त्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी युद्ध के जनक जार्ज डब्लू बुश ने 20 सितम्बर 2001 को वेस्ट प्वाइन्ट सैनिक छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा

''हमारी सुरक्षा के लिए आप जिस सेना का नेतृत्व करेंगे उसे एक ऐसी सेना में रूपान्तरित करने की जरूरत है जो एक क्षण की सूचना पर दुनिया के किसी भी अंधेरे कोने में हमला करने को तैयार रहे। और हमारी सुरक्षा के लिए हर एक अमरीकी का अग्रसोची और अटल होना जरूरी है। अपनी आजादी और जान की हिफाजत के लिए जरूरत पड़ने पर पहले ही कार्रवाई के लिए तैयार रहना जरूरी है।

''हमें 60 या उससे भी अधिक देशों में आतंकी गुटों का पता लगाना है। अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर शस्त्रीकरण का विरोध करना है और हर मामले में जरूरत के मुताबिक आतंक को मदद करने वाले शासकों का मुकाबला करना है।''

ओबामा उस भाषण के बारे में क्या कहेंगे?

सुरक्षा परिषद उन लोगों पर कौन से प्रतिबन्ध थोपेगी जिन्होंने इराक में लाखों लोगों का कत्ल किया और अफगानिस्तान में हर रोज औरतों-मर्दों और बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जहाँ हाल के दिनों में गुस्से से आग बबूला लोग मासूम बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ भारी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं?

आज ही 9 मार्च को एक खबर बताती है ''अफगानिस्तान में तालिबान और अन्तरराष्ट्रीय सेनाओं के बीच नौ साल से जारी युद्ध के दौरान पिछला साल नागरिकों के लिए सबसे भयावह साल रहा। इस साल वहाँ लगभग 2800 लोग मारे गये जो 2009 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध की मानवीय कीमत को रेखांकित करते हुए बुधवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।''

''पिछले कुछ वर्षों में तालिबान विद्रोहियों ने अपनी कार्रवाई तेज की है और अपनी स्थिति मजबूत की है। इन की गुरील्ला कार्रवाइयाँ इनके परम्परागत गढ़ों से आगे, दक्षिण और पूरब तक फैल गयी हैं।''

''अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहयोग मिशन द्वारा जारी संयुक्त वार्षिक रिपोर्ट में यह बताया गया कि वहाँ 2010 में कुल 2777 नागरिक मारे गये जो वर्ष 2009 की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है।

''राष्ट्रपति ओबामा ने 5 मार्च को 9 बच्चों की मौत के लिए अफगानी जनता को अपना ''गहरा शोक सन्देश'' दिया। आईएसएएफ के कमान्डर इन चीफ, अमरीकी जनरल डेविड पेट्रियस और रक्षा मन्त्री रॉबर्ट गेट्स ने भी इसी तरह का बयान जारी किया।''

''युएनएएमए की रिपोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि 2010 में वहाँ मरने वाले नागरिकों की संख्या उसी वर्ष लड़ाई में मरने वाले अन्तरराष्ट्रीय सेना के जवानों की संख्या से चार गुणा अधिक है।''

''2010 विदेशी सैनिकों के लिए भी युद्ध का सबसे भयानक साल रहा जिसके दौरान वहाँ 711 सैनिक मारे गये। यह इस बात का प्रमाण है कि अमरीका द्वारा वहाँ 30,000 कुमुक भेजे जाने के बावजूद तालिबानी गुरिल्लों ने पिछले वर्ष अपनी

कार्रवाई तेज की है।''

दस दिनों में जेनेवा और संयुक्त राष्ट्र संघ में वहाँ मानवाधिकार हनन के बारे में 150 से अधिक भाषण दिये गये जिन्हें टीवी, रेडियो, इन्टरनेट और पत्र-पत्रिकाओं ने लाखों बार दुहराया।

क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज ने 1 मार्च को जेनेवा में विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने भाषण में कहा

''मानव अन्तःचेतना किसी भी परिस्थिति में और कहीं भी निर्दोष लोगों की मौत को नामंजूर करती है। हम लीबिया में नागरिकों की मौत को लेकर दुनिया की चिन्ता का पूरी तरह समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि बिना विदेशी हस्तक्षेप के वहाँ हो रहे गृह युद्ध का शान्तिपूर्ण और सम्प्रभु समाधान निकाला जाये और उस राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की जाये।''

उस भाषण के कुछ एक अन्तिम वाक्य ध्यान देने योग्य हैं

''यदि अनिवार्य मानवाधिकार जीवन का अधिकार है, तो क्या सुरक्षा परिषद उन देशों की सदस्यता निलम्बित करने को तैयार है जो युद्ध छेड़ते हैं?''

''क्या यह उन देशों की सदस्यता निलम्बित करेगा जो हमलावर देशों को वित्तीय और सैनिक सहायता देते हैं, जिनके बल पर वे बड़े पैमाने पर जघन्य और इरादतन मानवाधिकारों के हनन और आम नागरिकों पर हमले की कार्रवाई में लिप्त रहते हैं, जैसा कि फिलीस्तीन में हो रहा है?''

''क्या यह उन शक्तिशाली देशों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो उच्च तकनोलॉजी, जैसे बमों और मानव रहित बम वर्षक विमानों का इस्तेमाल करके दूसरे देशों की सीमा के भीतर गैर कानूनी हमलों को अन्जाम देते हैं?''

''उन देशों का क्या होगा जो अपने देश की सीमा में गैर कानूनी गुप्त जेल बनाना स्वीकार करते हैं, गुप्त हवाई उड़ानों से अगवा किये गये लोगों को लाने-ले जाने की सुविधा देते हैं या यन्त्रणा देने की कारगुजारियों में भाग लेते हैं?''

''हम बोलिवारियाई नेता ह्यूगो शावेज और एएलबीए की साहसिक अवस्थिति के साझीदार हैं।''

''हम लीबिया में अन्दरूनी युद्ध के खिलाफ हैं तथा तत्काल शान्ति, जीवन का पूर्ण-सम्मान और सभी नागरिकों के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन बिना उस विदेशी हस्तक्षेप के जो इस टकराव को लम्बे समय तक जारी रखने और नाटो की स्वार्थपूर्ति में सहायक होगा।''

बराबरों की हिस्सेदारी

20 मार्च 2011

19 मार्च, शनिवार की शाम, एक राजसी भोज के बाद नाटो के नेताओं ने लीबिया पर आक्रमण करने का आदेश दिया। निश्चय ही अमरीका द्वारा सर्वोच्च नेतृत्व की अकाट्य भूमिका की दावेदारी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। यूरोप स्थित नाटो की अपनी नियंत्रण चौकी से एक उच्च अधिकारी ने एलान किया कि '''ओडिसी डाउन' शुरू होने वाला है।''

विश्व जनमत जापान की त्रासदी से मर्माहत था। भूकम्प, सुनामी और नाभिकीय दुर्घटना के शिकार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब तक हजारों लोग मारे गये, गायब हुए या विकीरण की चपेट में आ गये। नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल का बड़े पैमाने पर विरोध भी बढ़ने लगा।

इसी समय, दुनिया जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से बुरी तरह त्रस्त है। खाद्यान्न का अभाव और महँगाई, सैनिक खर्चे तथा प्राकृतिक और मानव संसाधनों की फिजूलखर्ची दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे वक्त में इस युद्ध का होना एक अत्यन्त समीचीन घटना है।

ओबामा द्वारा समूचे लातिन अमरीका की यात्रा को पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया, जनता ने इस पर शायद ही कहीं ध्यान दिया हो। ब्राजील और अमरीका के बीच परस्पर विरोधी स्वार्थों का होना अब एकदम स्पष्ट हो गया है।

हम भूल नहीं सकते कि रियो द जेनेरियो ने 2016 में होने वाले ओलम्पिक खेलों का आयोजक बनने के लिए शिकागो से प्रतिस्पर्धा की थी। ओबामा इस विशाल लातिन अमरीकी देश को अपने पक्ष में करना चाहते थे। उन्होंने ''ब्राजील के असाधारण उठान'' की चर्चा की जिसने अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी छाप

छोड़ी है। उन्होंने दुनिया में तीव्रतम विकासदर वाली अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने विशेषाधिकार मुक्त सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए ब्राजील का समर्थन करने की लेशमात्र वचनबद्धता भी नहीं जतायी।

ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी अमरीका द्वारा तटकर और सबसीडी के रूप में अपने देश के ऊपर थोपे जा रहे संरक्षणवादी उपायों के बारे में, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवरोध खड़ा कर रहे हैं, बेहिचक अपनी असहमति का इजहार किया।

अर्जेन्टीना के लेखक अतीलियो बोरोन कहते हैं :

''साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में ओबामा की सबसे ज्यादा रुचि अमाजोनिया पर अपने नियंत्रण को आगे बढ़ाना है। इस योजना की अनिवार्य शर्त यह है कि इस क्षेत्र में जो राजनीतिक और आर्थिक सहकार व एकीकरण बढ़ रहा है उसे भले ही वे रोक न पायें, लेकिन उसकी रफ्तार को धीमी करें। ऐसा इसलिए किसी इसी क्षेत्रीय सहयोग ने एएलसीए को बेजान बनाने तथा 2008 में बोलीविया और 2010 में इक्वाडोर में अलगाववादी षड़यंत्र और तख्ता-पलट को नाकाम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ओबामा के लिए यह भी जरूरी है कि वे इस क्षेत्र की अत्यंत आमूल-परिवर्तनवादी सरकारों (क्यूबा, वेनेजुएला, बोलीविया और इक्वाडोर) तथा, 'प्रगतिशील' सरकारों, मुख्यतः ब्राजील, अर्जेन्टीना और उरुग्वे के बीच फूट के बीज बोने की कोशिश करें।''

''इस ढीठ अमरीकी रणनीतिज्ञ के लिए अन्टार्कटिक की तरह ही अमेजन नदी की घाटी भी एक बेरोक-टोक प्रवेश वाला इलाका है जहाँ राष्ट्रीय सम्प्रभुता का सम्मान नहीं किया जाता।''

कल ओबामा चिली के लिए रवाना हुए। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने एल मरकूरियो अखबार को एक साक्षात्कार दिया जो आज ही रविवार को प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने पाप स्वीकार किया कि ''अमरीकी देशों में जारी वाद-विवाद'' जैसा कि वे हमें बताते हैं, लातिन अमरीका के साथ ''बराबरों की भागीदारी'' है जो वास्तव में स्तब्ध कर देता है, क्योंकि यह हमें बे ऑफ पिग पर भाड़े के सैनिकों द्वारा हमला किये जाने से ठीक पहले किये गये एलाइन्स फॉर प्रोग्रेस संस्था की याद दिला देता है।

ओबामा शब्दशः अपना पाप स्वीकार करते हैं कि इस गोलार्द्ध के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का सपना बराबरों की भागीदारी की अवधारणा पर आधारित है जिसे वे राष्ट्रपति बनने के पहले से ही आगे बढ़ा रहे हैं।

ओबामा ने कहा कि वे उन विशेष क्षेत्रों पर भी ध्यान देंगे जिनमें वे साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे आर्थिक विकास, ऊर्जा, सुरक्षा और मानवाधिकार...।

उन्होंने जोर देकर कहा कि इस सपने का लक्ष्य साझा सुरक्षा को बेहतर बनाना, आर्थिक अवसरों का विस्तार करना, भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करना और जिन लोकतांत्रिक मूल्यों के हम साझेदार हैं उनका समर्थन करना है।

...एक सुरक्षित स्थिर और समृद्ध गोलार्द्ध को बढ़ावा देना, जहाँ संयुक्त राज्य अमरीका और उसके भागीदार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में अपने दायित्वों में हिस्सा बांटते हैं...

जैसा कि हम देख सकते हैं, हर चीज बेहद खूबसूरत है, रीगन के रहस्यों की तरह ही दफना दिये जाने के लायक ताकि 200 सालों के भीतर वे प्रकाशित हो जायें।

समस्या यह है कि डीपीए संवाद एजेन्सी ने सूचित किया है कि 'ला तटसेरा' अखबार द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार ''...2006 में चिली की 43 प्रतिशत जनता नाभिकीय संयन्त्रों को नामंजूर कर रही थी।''

दो साल बाद नामंजूर करने वालों की तादात बढ़कर 52 प्रतिशत हो गयी और 2010 में यह 74 प्रतिशत तक पहुँच गयी। जापान में जो दुर्घटना हुई, उसके बाद आज ''86 प्रतिशत चिली निवासी'' नाभिकीय संयन्त्रों को नामंजूर करते हैं।

हम ओबामा से केवल एक सवाल पूछना चाहते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि उनके एक प्रख्यात पूर्ववर्ती रिचर्ड निक्सन ने वहाँ सत्तापलट और सल्वाडोर अलेन्दे की वीरतापूर्वक मौत तथा हजारों लोगों की यंत्रणा और हत्या को बढ़ावा दिया था, क्या श्रीमान ओबामा इसके लिए चिली की जनता से क्षमा याचना करेंगे!

नाटो का फासीवादी युद्ध

28 मार्च 2011

''लीबिया पर कब्जा करने की योजना'' ''मानव द्रोही मौत का ताण्डव'' और ''नाटो का अपरिहार्य युद्ध'' शीर्षक से अपने तीन विमर्श लेखों में 21 फरवरी से 3 मार्च के बीच हमने काफी विस्तार से जो बातें लिखी थीं, उनका पूर्वानुमान करने के लिए आपका दिव्यद्रष्टा होना जरूरी नहीं।

1936 में स्पेन का गृह युद्ध जिस घटना को सम्भवतः पिछले दिनों ढेर सारे लोग याद कर रहे होंगे, उसे शुरू करने वाले जर्मनी और इटली के फासीवादी नेता भी उसके बारे में इस हद तक खुली बेहयाई पर उतारू नहीं थे।

तब से आज तक 75 साल गुजर गये, लेकिन हमारे ग्रह पर मानव जीवन की 75 शताब्दियों या फिर 75 सहस्राब्दियों के दौरान भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी तुलना स्पेन के गृह युद्ध से की जा सके।

कभी-कभी ऐसा लग सकता है कि हममें से जो लोग इन मुद्दों पर शान्त मन से अपने विचार व्यक्त करते हैं, वे इन्हें बढ़ा-चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। मैं कहने का साहस करूँ, तो वास्तव में हम सहज भाव से यह मानते रहे हैं कि हम सभी लोगों को उस कपट और विराट अज्ञान के प्रति जागरुक होना चाहिए जिसमें आज पूरी मानवता को जकड़ा गया है।

1936 में लगभग बराबर की सैन्य शक्ति-वाली दो व्यवस्थाओं और विचारधाराओं के बीच तीखा टकराव था।

आज के हथियारों की तुलना में उस जमाने के हथियार एकदम खिलौने जैसे लगते थे। विनाशकारी शक्ति और स्थानीय घातक बलों को लगाये जाने के बावजूद, उन दिनों मानवता का अस्तित्व खतरे में नहीं था। आज तो पूरा का पूरा शहर और

यहाँ तक कि राष्ट्र भी वस्तुतः तबाह किया जाता रहा है। लेकिन आधुनिक विज्ञान और तकनोलॉजी के जरिये, मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती शक्तियाँ विकसित किये जाने के चलते सम्पूर्ण मानव जाति को कई-कई बार पूरी तरह खत्म कर दिये जाने का जैसा खतरा आज सामने है, वैसा पहले कभी नहीं था।

इन समकालीन सच्चाइयों को दिमाग में रखते हुए, शत-प्रतिशत सटीक निशाने वाले शक्तिशाली लेजर चालित रॉकेटों, ध्वनि की गति से दुगनी रफ्तार वाले लड़ाकू वमवर्षक विमानों, यूरेनियम द्वारा कठोर बनायी गयी धातुओं से आघात करने वाले प्रबल विस्फोटकों, जो वहाँ के निवासियों और उनकी भावी पीढ़ियों पर अनन्त काल तक दुष्प्रभाव डालते रहते हैं, इनके इस्तेमाल का लगातार समाचार पढ़ना सचमुच बेचैन कर देता है।

क्यूबा ने जेनेवा बैठक में लीबिया की आन्तरिक स्थिति के बारे में अपनी अवस्थिति बतायी थी। क्यूबा ने लीबिया में जारी झड़पों के राजनीतिक समाधान के विचार का बेहिचक समर्थन किया था और किसी भी विदेशी सैनिक हस्तक्षेप का साफ तौर पर विरोध किया था। एक ऐसी दुनिया में, जहाँ अमरीका और यूरोप की विकसित पूँजीवादी शक्तियों के बीच गठजोड़ आज जनता के संसाधनों और उनकी मेहनत की कमाई पर दिनों-दिन कब्जा जमाते जा रहा है, वहाँ कोई भी ईमानदार नागरिक, सरकार के प्रति उसका दृष्टिकोण चाहे जो भी हो, अपने देश में विदेशी सैनिक हस्तक्षेप के खिलाफ होगा।

लेकिन समकालीन परिस्थितियों में सबसे बड़ी विसंगति यह है कि उत्तरी अफ्रीका में नृशंस युद्ध शुरू होने से पहले वहाँ से 10,000 किमी दूर दुनिया के एक अन्य क्षेत्र में 9.0 रिक्टर पैमाने के भूकम्प से उत्पन्न सुनामी के बाद, दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके में एक नाभिकीय दुर्घटना हुई, जिसने अब तक जापान जैसे मेहनती राष्ट्र के 30,000 लोगों की जान ले ली। अब से 75 साल पहले ऐसी दुर्घटना नहीं हो सकती थी।

एक गरीब और अविकसित देश हैती में लगभग 7.0 रिक्टर पैमाने का भूकम्प आया था जिसमें 3,00,000 लोगों की जान गयी, असंख्य लोग घायल हुए और लाखों लोगों को नुकसान पहुँचा।

जापान की यह भयावह त्रासदी, फुकुशीमा नाभिकीय संयन्त्र में हुई दुर्घटना थी जिसके दुष्परिणामों का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। मैं केवल समाचार एजेंसियों द्वारा प्रकाशित कुछ मुख्य कहानियों की याद दिलाना चाहूँगा

एएनएसए फुकुशीमा-1 नाभिकीय संयन्त्र से ''अत्यन्त तीव्र और प्रभावी रूप से जानलेवा विकिरण'' हो रहा है, यह बात अमरीकी नाभिकीय संस्था न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष ग्रेगोरी जैक्जकों ने कही।

ईएफई भूकम्प के बाद एक जापानी संयन्त्र में गंभीर परिस्थिति से उत्पन्न, नाभिकीय खतरे ने पूरी दुनिया के नाभिकीय संयन्त्रों की सुरक्षा में सुधार करने और कुछ देशों को अपनी योजनाओं को ठप्प कर देने के लिए प्रेरित किया है।

रायटर जापान के विनाशकारी भूकम्प और गहराते नाभिकीय संकट के परिणामस्वरूप वहाँ की अर्थव्यवस्था को 200 अरब डॉलर तक का नुकसान हो सकता है, लेकिन दुनिया भर में इसका क्या प्रभाव होगा, इसका अन्दाजा लगाना कठिन है।

ईएफई जापान के फुकुशीमा नाभिकीय केन्द्र पर लगातार एक के बाद दूसरे रिएक्टर का खराब होना लम्बित नाभिकीय आपदा के भय को लगातार बढ़ा रहा है क्योंकि विकिरण युक्त रिसाव को नियन्त्रित करने के निराशाजनक प्रयासों से उम्मीद की कोई झलक नहीं मिली है।

ए एफ पी जापान के सम्राट अकीहीतो ने नाभिकीय संकट के इस चरित्र को लेकर चिन्ता प्रकट की है, जिसका पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है, इसने भूकम्प और सुनामी के बाद जापान के हजारों लोगों को मौत के मुँह में धकेल दिया तथा 5,00,000 लोगों को बेघर कर दिया। टोकियो इलाके में फिर भूकम्प की सूचना मिली है।

इनसे भी अधिक चिन्ताजनक मुद्दों की चर्चा करने वाली रिपोर्ट आयी हैं।

कुछ ने टोकियो के पेयजल में जहरीले रेडियोधर्मी आयोडीन होने का हवाला दिया है जो जापानी राजधानी के छोटे बच्चों के लिए पीने योग्य पानी में स्वीकृत मात्रा से दो गुना है। इनमें से एक रिपोर्ट कहती है कि टोकियो जो फुकुशीमा से 200 किमी से भी अधिक दूरी पर स्थित एक प्रान्त में बसा हुआ शहर है, वहाँ बोतलबन्द पानी का भंडार कम हो रहा है।

घटनाओं की यह शृंखला हमारी दुनिया में एक नाटकीय परिस्थिति सामने ला रही है। मैं लीबिया में युद्ध के बारे में अपना दृष्टिकोण खुलकर व्यक्त कर सकता हूँ।

उस देश के नेता के साथ मेरे राजनीतिक या धार्मिक विचारों का कोई मेल नहीं है। मैं मार्क्सवादी-लेनिनवादी हूँ और मार्ती का अनुयायी हूँ, जैसा कि मैंने पहले

ही कहा है।

मैं लीबिया को गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के एक सदस्य और संयुक्त राष्ट्रसंघ के लगभग 200 सदस्यों में से एक सम्प्रभु देश मानता हूँ।

कोई भी बड़ा या छोटा देश, एक ऐसे सैनिक संगठन की वायु सेना द्वारा जघन्य हमले का इस तरह शिकार नहीं हुआ था, जिसके पास हजारों लड़ाकू बमवर्षक विमान, 100 से भी अधिक पनडुब्बी, नाभिकीय वायुयान वाहक और धरती को कई बार तबाह करने में सक्षम शस्त्रास्त्रों का जखीरा है। हमारी प्रजाति के आगे ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आयी और 75 साल पहले भी इससे मिलती-जुलती कोई चीज नहीं रही है जब स्पेन को निशाना बनाकर नाजी बमवर्षकों ने हमले किये थे।

हालाँकि अपराधी और बदनाम नाटो अब अपने ''लोकोपकारी'' बमबारी के बारे में एक ''खूबसूरत'' कहानी गढ़ेगा।

अगर गद्दाफी ने अपनी जनता की परम्पराओं का सम्मान किया और अन्तिम साँस तक लड़ने का निर्णय लिया, जैसा कि उसने वादा किया है और लीबियाई जनता के साथ मिलकर मैदान में डटा रहा जो एक ऐसी निकृष्टतम बमबारी का सामना कर रही है जैसा आज तक किसी देश ने नहीं किया, तो नाटो और उसकी अपराधिक योजना शर्म के कीचड़ में धँस जायेगी।

जनता उसी आदमी का सम्मान करती है और उसी पर भरोसा करती है जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं।

अबसे 50 से भी अधिक साल पहले, जब संयुक्त राज्य अमरीका ने माल वाहक जहाज ''ला कोब्रे'' का विस्फोट करके सौ से भी ज्यादा क्यूबाइयों की हत्या की थी, तब हमारे लोगों ने घोषणा की थी पात्रिया या मूएर्ते (जन्म भूमि या मौत)। उन्होंने इसका निर्वाह किया और अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा दृढसंकल्प बने रहे।

''जो भी क्यूबा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा'' हमारे दौर के अत्यन्त यशस्वी योद्धाओं ने कहा ''उसके देश की मिट्टी खून से सन जायेगी।''

मैंने जिस स्पष्टता के साथ इस मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की उसके लिए आप हमें माफ करेंगे।

बेहतर और ज्यादा समझदार

31 मार्च 2011

स्थान और समय की कमी के चलते कल मैं बराक ओबामा द्वारा 28 मार्च, सोमवार को लीबिया युद्ध पर दिये गये भाषण के बारे में एक भी शब्द नहीं कह सका। मेरे पास उसके औपचारिक पाठ की प्रति है जिसे अमरीकी सरकार ने पत्रकारों को दिया था। उनके द्वारा कही गयी कुछ बातों को हमने रेखांकित कर दिया है। मैंने इसकी फिर से समीक्षा की और इस नतीजे पर पहुँचा कि यह इस लायक नहीं कि इस विषय पर ज्यादा कागज बर्बाद किया जाए।

मुझे 2002 में कार्टर ने अमरीका में पेड़ उगाने के बारे में जो बात कही थी वह याद आ रही है, क्योंकि वे अटलान्टा के निकट एक पारिवारिक फार्म के मालिक हैं। इस यात्रा के दौरान मैंने उनसे पेड़ उगाने के बारे में फिर पूछा और उन्होंने दोबारा बताया कि 3 x 2 मीटर की दूरी पर चीड़ का पेड़ लगाते हैं। एक हेक्टेयर में 1700 पेड़ लगते हैं जिन्हें 25 वर्षों बाद काटा जाता है।

कई साल पहले मैंने पढ़ा था कि 'द न्यूयार्क टाइम्स' का रविवारीय संस्करण 40 हेक्टेयर जंगल काटकर तैयार किया गया कागज निगल जाता है। कागज बचाने को लेकर मेरी चिन्ता का यही कारण है।

निश्चय ही ओबामा शब्दों और मुहावरों के बेजोड़ बाजीगर हैं। वे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखकर रोजी-रोटी चला सकते हैं। मैं उनके शिल्प से परिचित हूँ क्योंकि बहुत पहले, जब वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, मैंने उन्हें पहली बार पढ़ा और रेखांकित किया था। उस किताब का नाम था 'मेरे पिता के सपने'। मैंने आदर सहित उनको पढ़ा और कम से कम मैं उनकी तारीफ करूँगा कि वे पाठकों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए सही शब्दों और सटीक मुहावरों का चुनाव करते हैं।

क्षमा करें, मैं उनके कुतूहल की चाल को पसन्द नहीं करता, जिसके तहत वे अपने खुद के राजनीतिक विचारों को अन्त तक छुपाये रहते हैं। मैंने अन्तिम अध्याय में इस बात को न ढूँढने का विशेष प्रयास किया कि वे विभिन्न समस्याओं को लेकर क्या सोचते हैं; जो मानव इतिहास के इस मोड़ पर मेरे दिमाग के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। मुझे यकीन था कि गम्भीर आर्थिक संकट, भारी भरकम सैनिक खर्च और उनके रिपब्लिकन पूर्ववर्ती द्वारा नौजवानों का खून बहाया जाना उनके चुनावी विरोधी को हराने में मददगार होगा, बावजूद इसके कि अमरीकी समाज में नस्ली पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा है। मैं इस बात को लेकर भी सचेत था कि उनके सामने शारीरिक रूप से खत्म कर दिये जाने का भी खतरा है।

परम्परागत राजनीतिक परिपाटी की मजबूती के चलते उन्होंने मियामी के क्यूबा विरोधी मतदाताओं का समर्थन माँगा जिनका बहुमत उन बतिस्ता समर्थक प्रतिक्रियावादी लोगों के नेतृत्व के अधीन था जिन्होंने संयुक्त राज्य अमरीका को रिपब्लिकन में तब्दील कर दिया जहाँ 2000 में जार्ज डब्ल्यू बुश की जीत में चुनावी धोखाधड़ी निर्णायक भूमिका निभाती है और भविष्य के नोबेल पुरस्कार विजेता, क्लिंटन के समय उपराष्ट्रपति रह चुके राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी अल-गोर को कूड़े के ढेर में फेंक देती है।

न्याय की मूल भावना होती तो राष्ट्रपति ओबामा को प्रोत्साहित करती कि वे उस कुख्यात मुकदमे के परिणामों को संशोधित करते जिसने पाँच क्यूबाई देश-भक्तों को अमानवीय, क्रूर और खासतौर पर अन्यायपूर्ण ढंग से बन्दी बनाने का रास्ता तैयार किया था।

अमरीकी संसद में उनका सम्बोधन, ब्राजील, चिली और अलसल्वाडोर में तथा नाटो द्वारा लीबिया पर युद्ध थोपने के बारे में उनके भाषणों ने मुझे बाध्य कर दिया कि उनकी जीवनी से आगे, उनके उपर्युक्त भाषण को रेखांकित करूँ।

उस भाषण में सबसे बुरी चीज क्या है और उसके सरकारी पाठ में लगभग 2500 शब्दों की व्याख्या किस तरह की जाये?

देश के आन्तरिक दृष्टिकोण से, इसमें यथार्थवाद का जो अभाव है वह अपने प्रसन्नचित लेखक को उसके निकृष्टतम विरोधियों के हवाले कर देती है जो उसे अपमानित करना चाहते हैं और नवम्बर 2008 की चुनावी जीत का बदला लेना चाहते हैं। 2010 के अन्त में उन्होंने जो सजा दी थी उतने से संतुष्ट नहीं हैं।

विदेशी दृष्टिकोण से, बहुत सारे लोगों के लिए सुरक्षा परिषद, नाटो और यांकी

साम्राज्यवादियों का क्या अर्थ है, इसके बारे में दुनिया आज पहले से कहीं ज्यादा जागरुक हो चुकी है।

संक्षेप में बात रखने के लिए जिसका मैंने वादा किया है, मैं कहूँगा कि ओबामा ने अपने भाषण की शुरुआत इस स्वीकारोक्ति से की है कि वे ''अफगानिस्तान में तालिबान के आवेग को रोकने और दुनियाभर में अलकायदा के खिलाफ कार्रवाई करने'' की अपनी भूमिका निभा रहे हैं।

इसके बाद उन्होंने जोड़ा, ''पीढ़ियों तक संयुक्त राज्य अमरीका ने वैश्विक सुरक्षा के अवलम्ब और मानव स्वतंत्रता के हिमायती की एक अनोखी भूमिका निभायी है।''

जैसा कि पाठक जानते हैं, यह ऐसी बात है जिसकी सच्चाई का प्रमाण हम क्यूबाई, लातिन अमरीकी, वियतनामी और कई अन्य देशों की जनता ही दे सकती है।

आस्था की इस आडम्बरपूर्ण घोषणा के बाद ओबामा अपने समय का एक बड़ा हिस्सा गद्दाफी के बारे में बात करने में खपाते हैं, उनका भय और कारण, जिसके चलते अमरीका और इसके निकटतम सहयोगी, जैसे ''ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, इटली, स्पेन, ग्रीस और तुर्की उन सभी ने जो हमारी तरफ से दशकों तक लड़ाई लड़ी है...लीबियाई जनता की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी का पालन करना तय किया है।''

आगे वे जोड़ते हैं...''नाटो ने हथियारों की नाकेबन्दी और उड़ान वर्जित क्षेत्र को लागू करने की कमान सम्भाली है।''

इस निर्णय के उद्देश्यों की वे पुष्टि करते हैं ''इस व्यापक, नाटो-आधारित गठजोड़ की ओर संक्रमण के कारण इस अभियान के जोखिम और खर्चे हमारी सेना और हमारे करदाताओं पर बोझ काफी कम हो जाएगा।

''इसलिए जो लोग इस अभियान को चलाने की हमारी क्षमता पर संदेह करते हैं, उन्हें मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि अमरीका ने जो कहा है वही किया है और हम करेंगे।''

इसके बाद वे गद्दाफी के बारे में अपनी मनोग्रंथी और उन अन्तर्विरोधों की ओर लौटते हैं जो उनके दिमाग को परेशान कर रहे हैं ''गद्दाफी ने अब तक सत्ता नहीं छोड़ी है और जब तक वे ऐसा नहीं करते, लीबिया खतरनाक बना रहेगा।''

''यह सही है कि अमरीका हर उस जगह अपनी सेना का इस्तेमाल नहीं कर

सकता जहाँ-जहाँ दमन हो रहा हो और सैनिक हस्तक्षेप की कीमत और जोखिम को देखते हुए, हमें कार्रवाई की जरूरत के बरक्स अपने स्वार्थों को हमेशा मानना होगा।''

''अपने सैनिकों को जो कार्यभार हमने सौंपा है लीबियाई जनता के संरक्षण का...उसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति और अन्तरराष्ट्रीय समर्थन है।''

अपनी मनोग्रंथी को वे बार-बार दुहराते हैं ''इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें अमरीकी सैनिकों को जमीन पर उतारना पड़ सकता है, या फिर हवाई हमले में ढेर सारे नागरिकों को कत्ल करने का जोखिम उठाना होगा।''

''...हम इराक के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। लेकिन वहाँ सत्ता परिवर्तन में आठ साल लग गये, हजारों अमरीकी और इराकी लोगों की जान गयी और लगभग 10,00,000 खरब डॉलर खर्च हो गये।''

नाटो की बमबारी शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद, समाचार आया कि एक अमरीकी लड़ाकू विमान मार गिराया गया। बाद में किसी सूत्र से पता चला कि वह खबर सही थी। पैराशूट से किसी आकृति को उतरते देख, ग्रामीणों ने वही किया जो लातिन अमरीका में करने की परम्परा है वे उसे देखने जाते हैं और यदि किसी को जरूरत हो तो वे मदद भी करते हैं। कोई जान नहीं पाया कि वे क्या सोच रहे थे। वे मुसलमान ही हों यह जरूरी नहीं, वे खेत में काम कर रहे थे और बमबारी के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अचानक उस पायलट को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर से ग्रामीणों पर गोली चलायी गयी, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया लेकिन उन सबको मौत के घाट नहीं उतारा जैसा कि दुनिया जानती है, अरब लोग परम्परागत रूप से अपने शत्रुओं की भी तीमारदारी करते हैं, वे उन्हें अपने घरों में ले गये और वापस जाते हुए उनकी ओर से पीठ फेर ली ताकि वे जिस रास्ते जा रहे हैं, यह देख न पायें। कोई डरपोक और गद्दार भी सामाजिकता की ऐसी भावना का इजहार नहीं कर सकता।

केवल ओबामा ही उस विदेशी सिद्धान्त के बारे में सोच सकते हैं जिसे उन्होंने अपने भाषण में शामिल किया है, जिसे इन पंक्तियों में देखा जा सकता है।

''ऐसा भी समय होगा जब भले ही हमारी सुरक्षा को सीधे खतरा न हो, लेकिन हमारे स्वार्थों और हमारे मूल्यों पर खतरा हो...हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अमरीका को अक्सर सहायता के लिए बुलाया जाएगा।

''ऐसे मामलों में, हमें कार्रवाई करने से डरना नहीं चाहिए लेकिन कार्रवाई का बोझ अकेले अमरीका का नहीं होना चाहिए। बल्कि जैसा लीबिया में, जहाँ हमारा

कार्यभार सामूहिक कार्रवाई के लिए अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को गतिशील बनाना है।''

लीबिया में हमने ऐसे ही नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। निश्चय ही, यदि हम गठबन्धन के अंग के रूप में काम करते हैं तो भी किसी सैनिक कार्रवाई का जोखिम काफी अधिक होगा। ऐसे ही जोखिम का सामना करना पड़ा जब लीबिया में हमारे एक हवाई जहाज ने गड़बड़ी की। फिर भी जब हमारा एक वायु सैनिक पैराशूट से जमीन पर उतरा, उसे देश में जहाँ के नेता ने अक्सर अमरीका को दानव के रूप में पेश किया एक ऐसा इलाका जिसका हमारे देश के साथ इतना कठिन इतिहास रहा है उस अमरीकी ने वहाँ कोई दुश्मन नहीं पाया। इसके बदले उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसे गले लगाया। एक नौजवान लीबियाई जो उसकी सहायता के लिए आया, उसने कहा, ''हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम उन लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे आकाश की सुरक्षा कर रहे हैं।''

''यह उस इलाके की तमाम आवाजों में से एक है जहाँ की नयी पीढ़ी को अपने अधिकारों और अवसरों से वंचित होना अब और स्वीकार नहीं।''

''हाँ, यह बदलाव कुछ समय के लिए दुनिया को थोड़ा और जटिल बना देगा। प्रगति असमान होगी और विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न स्तर के बदलाव आएँगे। ऐसी भी जगहें हैं, जैसे मिस्र, जहाँ यह बदलाव हमें प्रेरित करेगा और हमारी उम्मीदों को बढ़ायेगा।''

हर कोई जानता है कि मुबारक अमरीका का सहयोगी था और जब ओबामा ने 2009 में कैरो विश्वविद्यालय का दौरा किया था, तब वे इस बात से अनजान थे कि मुबारक ने मिस्र में अरबों डॉलर की चोरी की है।

वे अपनी दिलचस्प कहानी को रखते हैं ''...हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में इतिहास आगे बढ़ रहा है और नौजवान लोग राह दिखा रहे हैं। क्योंकि जहाँ कहीं भी जनता आजाद होने को लालायित है, वे अमरीका को अपना दोस्त पाएँगे, यही विश्वास, ये ही विचार अमरीकी नेतृत्व का सच्चा पैमाना है।''

''...विदेशों में हमारी ताकत, देश के भीतर हमारी ताकत पर टिकी है। यही हमारा ध्रुवतारा होना चाहिए हमारे लोगों में अपनी ताकत हासिल करने की क्षमता, स्रोतों का सही उपयोग, अपनी समृद्धि बढाना, जो हमारी शक्ति का अक्षय स्रोत है और उन मूल्यों पर चलना जो हमें इतना प्यारा है।

''और हमें आत्मविश्वास और आशा के साथ भविष्य की और देखना है, न

केवल अपने देश के भीतर बल्कि उनके लिए भी जो दुनिया भर में आजादी के लिए तरस रहे हैं।''

इस भड़कीली कहानी ने बरबस मेरे मस्तिष्क में टी पार्टी को ला दिया, सिनेवर बॉब मेनेन्डेज और ख्यातिलब्ध एलीना रोस, नीच हुँडारिन जिसने कानून की धज्जी उड़ाते हुए अगवा किये गये क्यूबाई बालक एसियान गोन्जालेज को बंधक बनाया था। आज वही औरत अमरीकी संसद की विदेशी मामले की समिति की कुर्सी पर विराजमान है।

गद्दाफी बार-बार यह कह रहे हैं कि अल कायदा उनके साथ लड़ाई लड़ रहा है और लीबिया की सरकार के खिलाफ अपने लड़ाकों को भेज रहा है, क्योंकि गद्दाफी ने आतंक के खिलाफ युद्ध में बुश का समर्थन किया था।

अतीत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध के दौरान उस संगठन के साथ अमरीकी गुप्तचर सेवाओं के बहुत अच्छे सम्बन्ध थे और इसीलिए उसके पास सीआईए के काम करने के तौर-तरीकों के बारे में अनुभवों का खजाना है।

क्या होगा, यदि गद्दाफी का दावा सही होगा? ओबामा अमरीका की जनता के सामने इस बात की क्या व्याख्या करेंगे कि जमीनी लड़ाई में काम आने वाले हथियारों का एक हिस्सा बिन लादेन के आदमियों के हाथों में चला गया?

क्या लीबिया में युद्ध नहीं बल्कि शान्ति को प्रोत्साहित करने के लिए लड़ना कहीं बेहतर और बुद्धिमानी का काम नहीं होता?

एक आग जो सबको जला सकती है

27 अप्रैल 2011

गद्दाफी के राजनीतिक विचारों से आप सहमत हो या असहमत, लेकिन एक स्वतंत्र देश के रूप में लिबिया के अस्तित्व और संयुक्त राष्ट्र संघ की उसकी सदस्यता पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है।

दुनिया अभी उस मंजिल तक नहीं पहुँची है, जो मेरे विचार से हमारी मानव प्रजाति के बचे रहने की जरूरी शर्त है कि इस ग्रह के भौतिक संसाधन सभी लोगों के लिए सुलभ हों। हमारी जानकारी में पृथ्वी के अलावा पूरे सौर-मंडल में कोई और ग्रह नहीं है, जहाँ जीवन की अत्यन्त मूलभूत परिस्थितियाँ मौजूद हों।

संयुक्त राज्य अमरीका ने हमेशा ही खुद को सभी नस्लों, सभी आस्थाओं और सभी राष्ट्रीयताओं के लिए गोरे, काले, पीले, इण्डियन (मूल निवासी) और मिश्रित नस्लें, बिना किसी भेदभाव के, जो भी इसके सरहद के भीतर थे, सबके लिए घुलने-मिलने वाली जगह बनाने का प्रयास किया। वहां सिर्फ गुलाम और गुलामों के मालिक तथा धनी और गरीब के बीच भेदभाव बना रहा। उसके उत्तर में कनाड़ा दक्षिण में मैक्सिको, पूरब में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशान्त महासागर, अलास्का, प्यूर्तोरिको और हवाई तो महज ऐतिहासिक संयोग थे।

जिस बात ने मामले को पेंचीदा बना दिया है वह यह कि जो लोग एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ रहे हैं उनकी पवित्र इच्छाओं को यह समाविष्ट नहीं करता, जिसका उतना ही सम्मान किया जाना न्यायोचित है जितना किसी धार्मिक आस्था का। हमारी प्रजाति के क्षणभंगुर अस्तित्व को समाप्त करने के लिए सिर्फ तापनाभिकीय संयन्त्रों में इस्तेमाल किये जाने वाले सम्वर्धित यूरेनियम से जिससे एक खास तरह का विकिरणशील समस्थानिक तत्व (आइसोटॉप्स) उत्पन्न होता है।

और जिनका प्रकृति में कोई अस्तित्व नहीं होता उसकी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा ही काफी होगी। इन रेडियोधर्मी कचरों की दिनों-दिन बढ़ती मात्रा को सुदृढ़ कंक्रीट और इस्पात के ताबुत में दफन करना तकनोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

चेरनोबिल दुर्घटना या जापान में भुकम्प जैसी घटनाएँ इन जानलेवा जोखिमों को प्रकट करती हैं।

आज मैं जिस पर बात करना चाहूँगा, वह मुद्दा यह नहीं लेकिन वेनेजुएला टेलीविजन पर वाल्टर मार्टिनेन का कार्यक्रम ''योसिडर'' देखकर कल मैं कितना हतप्रभ था, जिसमें अमरीकी रक्षा मंत्रालय के प्रमुख राबर्ट गेट्स और लिबिया के खिलाफ नाटो द्वारा छेड़े गये आपराधिक युद्ध पर चर्चा करने अमरीका आये ब्रिटिश रक्षा मंत्री लियाम फॉक्स के बीच बैठक की फिल्मायी गयी छवियाँ दिखाई गयी थीं। इस पर विश्वास करना काफी मुश्किल था कि जैसे ब्रिटिश मंत्री ने ''ऑस्कर'' जीता हो। वे बेहद घबराये हुए थे। बहुत तनाव में थे, विक्षिप्त की तरह बातें कर रहे थे और ऐसा आभास करा रहे थे जैसे वे शब्दों को बड़ी मुश्किल से उगल रहे हों।

निश्चय ही वे पेन्टागन के प्रवेश द्वार पर पहुँचे जहाँ गेट्स उनकी अगवानी करने के लिए होठों पर मुस्कान लिए प्रतिक्षा में खड़े थे। दोनों देशों के झण्डे एक प्राचीन ब्रिटिश उपनिवेशवादी साम्राज्य का झंडा और दूसरा उसके सौतेले बेटे संयुक्त राज्य अमरीकी साम्राज्य का झण्डा प्रवेश द्वार के दोनों ओर ऊँचाई पर फहरा रहे थे। दोनों देशों के राष्ट्रगान बज रहे थे। मेजबान देश ने दाहिना हाथ छाती पर रखकर श्रम साध्य और भव्य सैनिक सलामी का समारोह पूरा किया। यह शुरूआती कार्यक्रम था। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अमरीकी सुरक्षा भवन के भीतर कदम रखा। अनुमानतः उन दोनों ने काफी देर तक बातें की। जिन छवियों को मैंने टेलीविजन पर देखा, उनके मुताबिक दोनों लोग अपने-अपने हाथ में भाषण की प्रति लेकर वापस आये जो निश्चय ही पहले से तैयार किया हुआ था।

इस पूरे परिदृश्य का संदर्भ वर्दीधारी सैनिकों से तैयार किया गया था। बायीं ओर मैंने एक लम्बा छरहरा नौजवान सैनिक देखा, जिसका लाल माथा सफाचट था जो एक काला टोप पहने था। जिसका ऊपरी सिरा उसके गले तक खिंचा हुआ था और जो अपनी रायफल की संगीन को प्रदर्शित कर रहा था। वह पलके नहीं झपका रहा था और लगता था कि वह साँस भी नहीं ले रहा है। यह उस सैनिक की आकृति थी जो अपनी राइफल की गोली या एक लाख टन की टीएमटी की विध्वंशकारी क्षमता

वाला नाभिकीय रॉकेट दागने को तत्पर हो। गेट्स ने मुस्कान बिखेरते हुए और मेजबान का स्वाभाविक शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए बात की। ब्रिटिश आदमी ने जैसा मैंने ऊपर वर्णन किया उस मनःस्थिति में बात की।

मैंने आम तौर पर ऐसी भयावह कोई चीज नहीं देखी। वह अपनी घृणा, निराशा और उन्माद का वमन कर रहा था और लीबियाई नेता के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था और उनसे बिना शर्त आत्मसमर्पण का अनुरोध कर रहा था। वह बहुत क्रुद्ध था क्योंकि नाटों के युद्ध विमान 72 घण्टों में लीबियाई प्रतिरोध को कुचल पाने में असमर्थ रहे थे।

उसमें बस विंस्टन चर्चिल की तरह इस चित्कार की कमी दिखाई दे रही थी ''खून पसीना और आँसू'', जब उसने इस बात की गणना की थी कि नाजी युद्ध विमानों की उसके देश को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन इस मामले में नाजी-फासीवादी भूमिका नाटो द्वारा दुनिया के लिए अब तक अज्ञात अत्याधुनिक विमानों के जरिये बमबारी के हजारों अभियानों के साथ निभाई जा रही है।

इन सबको मात देते हुए अमरीकी प्रशासन ने अफगानिस्तान की तरह ही लीबियाई आदमियों, औरतों और बच्चों का कत्ल करने के लिए हजारों किमी दूर पश्चिमी यूरोप से ड्रॉन बमवर्षकों के इस्तेमाल की इजाजत दी, लेकिन इस बार एक अरब-अफ्रीकी देश के खिलाफ और करोड़ों यूरोप वासियों की आँखों के सामने और वह भी संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम पर।

रूस के प्रधानमंत्री ब्लादिमीर पुतिन ने कल कहा कि युद्ध की ये कार्रवाइयाँ गैर-कानूनी हैं और वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित सहमति के दायरे से बाहर हैं।

लीबियाई जनता पर बर्बर हमला जिसने नाजी-फासीवादी चरित्र ग्रहण कर लिया है, इसे तीसरी दुनिया के किसी भी देश पर आजमाया जा सकता है।

मैं सचमुच लीबिया द्वारा किये गये प्रतिरोध को देखकर दंग रह गया।

युद्धरत संगठन अब गद्दाफी पर निर्भर हैं। अगर वे प्रतिरोध करते हैं और उनकी माँगों के आगे समर्पण नहीं करते तो वे अरब राष्ट्रों की एक महान विभूति के रूप में इतिहास में शामिल होंगे।

नाटो एक ऐसी आग को कुरेद रहा है जो सबको जलाकर खाक कर देगी।

बर्बर और उपद्रवी उत्तरी अमरीका

23 अप्रैल 2011

14 अप्रैल के गिरोन की लड़ाई के विषय में अपने विचारों को वादे के मुताबिक अच्छी तरह लगातार लिखने के लिए मैं ढेर सारी सामग्री और पुस्तकें पढ़ रहा था। मैं एक दिन पहले के समाचारों पर नजर डाल रहा था जो हर रोज की तरह ही प्रचुर मात्रा में थी। किसी भी सप्ताह आप समाचारों का पहाड़ जमा कर सकते हैं जिसका दायरा जापान में भूकम्प से लेकर पेरू के पूर्व राष्ट्रपति अलबर्टो फूजीमोरी की बेटी को हराकर ओलान्ता हुमाला की जीत तक, कुछ भी हो सकता है।

पेरू चाँदी, ताम्बा, जस्ता, टिन और अन्य अयस्कों का बड़ा निर्यातक है। इसके पास यूरेनियम का विपूल भंडार है, पार-राष्ट्रीय कम्पनियाँ उसका दोहन करना चाहती हैं। संबर्धित यूरेनियम से इतने भयंकर हथियार बनाये जा सकते हैं जिसके बारे में मानवता को अब तक कुछ नहीं पता। साथ ही इसे नाभिकीय उर्जा संयन्त्रों के लिए ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका पारिस्थितिक वैज्ञानिकों की लाख चेतावनियों के बावजूद अमरीका, यूरोप और जापान द्वारा तेजी से निर्माण किया जा रहा है।

निश्चय ही इन सबके लिए पेरू को दोष नहीं दिया जा सकता। पेरूवियाई लोगों ने उपनिवेशवाद, पूँजीवाद या साम्राज्यवाद का अविष्कार नहीं किया। हम अमरीकी जनता को भी दोष नहीं दे सकते जो खुद ही उस व्यवस्था की शिकार है, जिसने ऐसे परम सनकी राजनेताओं को उत्पन्न किया है जो इससे पहले इस ग्रह के लिए अन्जान थे।

पिछले 8 अप्रैल को दुनिया के मालिकों ने ''मानवाधिकारों के उल्लंघन'' पर अपनी परम्परागत वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के ऊपर चीन की राज्य परिषद ने जो प्रतिक्रिया दी है उसके आधार पर क्यूबा के मैनुएल इ.येये द्वारा 'रिबेलियन' वेबसाइट पर एक सरसरी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस दस्तावेज में ढेर सारे तथ्य दिये गये हैं जो अमरीका में मानवाधिकारों की अनर्थकारी स्थिति

को दर्शाते हैं।

''... अमरीका ऐसा देश है जो अपनी ही सरहदों के भीतर और समूची दुनिया में मानवाधिकारों पर सबसे ज्यादा हमले करता है। यह उन राष्ट्रों में से एक है जो अपने देशवासियों के जीवन, सम्पत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा की सबसे कम गारंटी करते हैं।

''अमरीका में हर पाँच में से एक व्यक्ति प्रतिवर्ष अपराध का शिकार होता है। धरती पर किसी भी देश की अपराध दर इससे अधिक नहीं है। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक 12 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग 4300,000 हिंसक कार्रवाइयों के शिकार हुए। देश के चार सबसे महत्त्वपूर्ण शहरों फिलाडेल्फिया, शिकागो, लॉस एन्जेल्स और न्यूयार्क में अपराध भयावह तरीके से बढ़ा है। अन्य बड़े शहरों सेन्ट लुइस और डेट्रोइट में भी पिछले साल की तुलना में कुख्यात अपराधों में वृद्धि दर्ज की गयी।

''सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना संवैधानिक अधिकार है और राज्य सरकारें इसकी अवहेलना नहीं कर सकतीं। लगभग 30 करोड़ की आबादी में से 9 करोड़ लोगों के पास 20 करोड़ हथियार हैं।

''देश में हथियारों से कुल 12,000 मानव-हत्या के मामले दर्ज किये गये जबकि 47 प्रतिशत डकैतियों को भी हथियारों के सहारे ही अंजाम दिया गया।

''देश-भक्ति कानून के'' ''आतंकी गतिविधियाँ'' अनुच्छेद के अन्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति से जुर्म कबूल करवाने के लिए यंत्रणा देना और नरम हिंस्सा आज प्रचलन में है। 266 लोगों के मामले में अन्यायपूर्ण सजा के प्रमाण मिले हैं जिनमें से 17 लोगों को जिन्हें फाँसी की सजा दी गयी थी, डीएनए जाँच के कारण निर्दोष ठहराये गये।

''वाशिंगटन, इन्टरनेट में आजादी की वकालत करता है ताकि वह नेटवर्कों के नेटवर्क का इस्तेमाल दबाव और अधिपत्य के एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक हथियार की तरह कर सके, लेकिन अपनी सरहद के भीतर साइबर स्पेस में कठोर नियंत्रण थोपता है और विकीलीक्स और इसके खुलासों द्वारा दी गयी चुनौतियों से निपटने के लिए छलपूर्वक कानूनी घेराबंदी की कोशिश करता है।

''बेरोजगारी की ऊँची दर के कारण गरीबी में जीने वाले अमरीकी नागरिकों की संख्या के नये कीर्तिमान बन रहे हैं। पिछले साल हर आधे में से एक नागरिक मुफ्त भोजन कूपन पर आश्रित था।

''बेघरों के लिए आश्रय स्थलों में गुजर-बसर करने वाले परिवारों की संख्या में 7 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। उन परिवारों को लम्बे समय तक आश्रय स्थलों में

ही रहना पड़ता है। इन बेघर परिवारों के ऊपर हिंसक अपराधों की संख्या में बेरोक-टोक वृद्धि हो रही है।

''नस्लवादी भेदभाव सामाजिक जीवन के हर पहलू में पसरता जा रहा है। अल्पसंख्यक समूहों के साथ कार्यस्थल पर भेदभाव किया जाता है। उनके साथ अपमान-जनक व्यवहार होता है तथा पदोन्नति, सुविधाओं और श्रमिक चयन की अन्य प्रक्रियाओं में उनका ध्यान नहीं रखा जाता। एक तिहाई काले लोग कार्यस्थल पर भेदभाव के शिकार होते हैं, जब कि केवल 16 प्रतिशत लोग ही शिकायत दर्ज कराने का साहस कर पाते हैं।

''गोरे लोगों में बेरोजगारी की दर 16.2 प्रतिशत है, हिस्पानी और एशियाई लोगों में 22 प्रतिशत और काले लोगों में 33 प्रतिशत है। अफ्रीकी अमरीकी और लातिन अमरीकी लोगों की जनसंख्या वहाँ के निवासियों का 41 प्रतिशत है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अफ्रीकी अमरीकी लोगों की संख्या गोरे लोगों से 11 गुना अधिक है।

''90 प्रतिशत महिलाएँ अपने कार्य स्थल पर किसी न किसी तरह के लैंगिक भेदभाव से पीड़ित हुई हैं। 2 करोड़ औरतें बलात्कार की शिकार हुई हैं। वहाँ की लगभग 60,000 महिलाएँ किसी न किसी तरह के यौन आक्रमण या हिंसा से पीड़ित हैं।

''विश्वविद्यालय में पढ़नेवाली पाँच में एक छात्रा के साथ यौन अत्याचार हुआ है और विश्वविद्यालय परिसर में होने वाले बलात्कार के 60 प्रतिशत मामले महिला छात्रावास के अन्दर होते हैं।

''10 में से 9 समलैंगिक, उभयलिंगी या परा-लैंगिक विद्यार्थी स्कूल में उत्पीड़ित किये जाते हैं।

''रिपोर्ट का एक अध्याय हमें इस बात का स्मरण कराता है कि अमरीकी सरकार अपने देश की सीमा से बाहर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कितना जिम्मेदार है। अमरीका की अगुआई में इराक और अफगानिस्तान पर थोपे गये युद्धों के चलते इन देशों की नागरिक आबादी के बीच से पीड़ित व्यक्तियों के आसमान छूते आँकड़े सामने आये हैं।

''अमरीकी आतंक विरोधी कार्रवाइयों में कैदियों के खिलाफ अत्याचार की घिनौनी घटनाएँ तथा ग्वाटेनामों और दुनिया के दूसरे इलाकों में नजरबन्दी के ठिकानों पर बिना किसी आरोप या मुकदमे के अनिश्चित समय तक बन्दी बनाकर रखना शामिल है जो तथाकथित ''अति महत्त्वपूर्ण बंदियों'' से पूछताछ के लिए बनाये गये थे और जहाँ उत्पीड़न के निकृष्टतम तौर-तरीके आजमाये जाते हैं।

''चीनी दस्तावेज हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि अमरीका ने विश्व

जनमत का अनादर करते हुए अपने अस्तित्व को बनाये रखने और विकास करने के क्यूबाई जनता के अधिकार का उलंघन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में लगातार 19 वर्षों तक दुनिया के देशों ने क्यूबा के पक्ष में आवाज उठाई और ''क्यूबा के खिलाफ आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय नाकेबन्दी को समाप्त करना जरूरी बताया'', जिसका अमरीका ने सम्मान नहीं किया।

''संयुक्त राज्य अमरीकी कई अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलनों का अनुमोदन करने में असफल रहा है, जैसे आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन, महिलाओं के खिलाफ हर तरह के भेदभाव की समाप्ति के लिए सम्मेलन, विकलांग लोगों के अधिकारों पर सम्मेलन और बच्चों के अधिकारों पर सम्मेलन।

''चीन सरकार द्वारा रिपोर्ट में शामिल किये गये आँकड़े दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में अमरीका की घृणित कार्रवाइयाँ उसे ''दुनिया भर में मानवाधिकारों का न्यायधीश'' के रूप में अयोग्य ठहराती हैं। उसकी ''मानवाधिकार कूटनीति'' महज दोगलापन और ढकोसलेबाजी है जो इसके रणनीतिक साम्राज्यवादी स्वार्थों की पूर्ति में सहायक है। चीनी सरकार ने अमरीकी सरकार को सलाह दी है कि वह अपने खुद की मानवाधिकार परिस्थितियों में सुधार लाये इस क्षेत्र में अपनी कारगुजारियों की जाँच करे और उनमें बदलाव लाये, तथा मानवाधिकार के बहाने दूसरे देशों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए जिस तरह अधिपत्य की कार्यवाई करता है, उस पर रोक लगाये।''

हमारी राय में विश्लेषण की महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की भर्त्सना एक ऐसे दस्तावेज में की गयी है जिसे चीन की सरकार ने जारी किया है। जहाँ कि आबादी 1,34 करोड़ है और जिसकी मौद्रिक नीधि 2,000 अरब डॉलर है। चीन के वाणिज्यिक सहयोग के बिना साम्राज्य डूब जायेगा। मेरी राय में हमारी जनता को चीनी सरकार की परिषद द्वारा जारी इस दस्तावेज़ में शामिल सही-सही आँकड़ों को जानना महत्त्वपूर्ण है।

यदि वे बातें क्यूबा ने कही होती तो उनका इतना महत्त्व नहीं होता। हम तो पिछले 50 वर्षों से उन पाखण्डों की भर्त्सना करते ही आ रहे हैं।

आज से 116 साल पहले 1895 में मार्ती ने कहा था

''...जिस रास्ते को हमें बंद करना है और जो हमारे खून से बंद हो रहा है, हमारे अमरीकी राष्ट्रों को उस बर्बर और उपद्रवी उत्तरी अमरीका का पिछलग्गू बनाने का रास्ता है, जो हमसे बेहद नफरत कर रहा है...''

''मैं उस प्रेत के अंदर पैठ कर जिया हूँ और मैं इसकी आंत के पेचों को जानता हूँ।''

■